



हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित



समाचार ही नहीं, विचार भी

सोने का सच्चा भाव

आनंद का सच्चा भाव

18 कैरेट रेट (75.00%)	= ₹105540/-
22 कैरेट रेट (91.60%)	= ₹128900/-
24 कैरेट रेट (99.99%)	= ₹140706/-

सोने का भाव* प्रति 10 ग्राम | 6S1 Extra

anand Jewels

Pandri, Raipur

सरगुजा

मानसून ने बढ़ाई किसानों की चिंता, सूख रहे बीजों के अंकुर

मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता में डाल दिया है। प्री-मानसून की बारिश के बाद खरीफ फसलों के लिए किसानों ने अपने खेतों को तैयार कर लिया है लेकिन बारिश के अभाव में न तो बुनाई कर पा रहे हैं न ही अभी तक धान का बीड़ा ही लगा पाए हैं। अवर्षा की स्थिति को देखते हुए विकासखण्ड मैनापाट, सीतापुर, बतौली एवं लुण्ड्रा में बड़ी संख्या में किसानों ने बीड़ा तैयार न कर सीधे अपने खेतों में धान के बीजों की सूखी बुनाई कर दी है लेकिन चिलचिलाती धूप निकलने एवं खेतों की नमी सूख जाने के कारण धान के अंकुर झुलस जा रहे हैं। किसानों ने मक्का सहित अन्य फसलों की बुनाई कर दी है, कुछ ने धान का थरहा भी लगाया है लेकिन खेतों में दरार पड़ने के कारण फसल तेजी से झुलस रही है।

रायगढ़

बोनी के बाद सूख गए 40 फीसदी अंकुरण, 20 दिन पिछड़ गई खेती



रायगढ़। जिले के किसानों ने रोपा के बजाए खेतों में बोनी तो 20 दिन पहले कर दी थी लेकिन बारिश नहीं होने से अंकुरण 40 फीसदी अब सूख चुके हैं। हालात यह है कि अब खेतों में किसानों को दोबारा बुनाई करनी पड़ेगी। बारिश नहीं होने से करीब 20 दिन खेती का काम पिछड़ चुका है। इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। दूसरी ओर बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में बड़े धान **शेष पेज 6 पर**

बिलासपुर :खेती पर संकट

अब तक केवल 5 हजार हेक्टेयर में बुआई

मानसून सक्रिय होने में विलंब होने और औसत से कम बारिश होने के कारण धान की बोनी पिछड़ गई है। किसान सूखे खेतों में ट्रैक्टर से जोताई तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन सूखी होने के कारण बोनी नहीं कर पा रहे हैं। जून से अब तक जिले में केवल 5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जबकि पिछले 10 वर्षों के औसत के हिसाब से जून माह में 150 मिमी बारिश होती है, नतीजा यह है कि जिले में अब तक सिर्फ 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही धान की बोनी हो सकी है, जबकि सामान्य स्थिति में जून के अंतिम **शेष पेज 6 पर**

ट्यूबवेल वाले तैयार कर रहे नर्सरी

कृषि उप संचालक पीडी हथेश्वर के अनुसार जिनके पास ट्यूबवेल की सुविधा है, वे नर्सरी तैयार कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। श्री हथेश्वर के अनुसार अभी देर नहीं हुई है, लेकिन हालात ऐसे ही रहने **शेष पेज 6 पर**

कांकेर : कम बारिश ने खरीफ फसल की रफ्तार की धीमी



अलनीनो के प्रभाव और जून के अंतिम सप्ताह तक सामान्य से कम बारिश ने कांकेर जिले में खरीफ सीजन की रफ्तार धीमी कर दी है। कांकेर जिले के मैदानी इलाकों में जहां कुछ हद तक बुआई हुई है, वहीं अतागढ़, कोयलीबेड़ा और दुर्गुकोंदल जैसे आदिवासी विकासखंडों में बारिश की कमी के **शेष पेज 6 पर**

रूठे मेघ, सहमे किसान, छत्तीसगढ़ में पिछड़ी खेती, कहीं 10, कहीं 15 फीसदी ही बुआई

गिलाई-देवीलाल साहू/ राजनांदगांव- हफ्तीज खान/ कवर्धा-महेश मिश्रा/ गरियाबंद- गोरेलाल सिन्हा/ धमतरी-दीपनारायण शर्मा/ कांकेर-विजय पांडेय बिलासपुर-कोमल सिंह/कोरबा-राकेश श्रीवास्तव/अंबिकापुर-अजय नारायण पांडेय/रायगढ़-स्वतंत्र महंत/ जांजगीर-अभिषेक शुक्ला की विशेष रिपोर्ट

धमतरी: बोनी के बाद सूखे पड़े हैं खेत

बारिश की बेरुखी से खेती किसानों पिछड़ गई है। किसान खेतों में धान छिड़ककर अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश बुंदालाबी से आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को बीज के खराब होने का डर सता रहा है।



उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। अलनीनों के असर से धमतरी जिले में सूखा पड़ा हुआ है। मानसून तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। उधर खरीफ की बोनी का समय निकलता जा रहा है। किसान कामता सेन, मुरारजी साहू, चंद्रहास साहू ने बताया कि धान की बोनी के लिए आदर्श **शेष पेज 6 पर**



कोरबा : अलनीनो के असर से सूखे जैसे हालात जिले में 22 सौ हेक्टेयर घटा बोनी का रकबा

मानसून की बेरुखी का असर अब खेती में दिखने लगा है। जून का महीना बीतने को है, बारिश न होने की स्थिति को देखते हुए आंशिक सूखे की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष बोनी का रकबा 22 सौ हेक्टेयर कम कर दिया है। इससे फसल की पैदावार भी कम होगी। आने वाले दिनों में भी अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो बोनी रकबा और भी कम हो सकता है। अल्प वर्षा को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान **शेष पेज 6 पर**



कम हुई बोनी

बीते वर्ष की तुलना में कम हुई बोनी अल्प वर्षा के कारण आंशिक सूखे की स्थिति निर्मित होने लगी है। किसानों को धान की जगह अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जून महीने तक बीते वर्ष बोनी रकबा 10 हजार हेक्टेयर पहुंच चुका था। इस वर्ष बोनी रकबा 7 हजार 200 के लगभग हुआ है। यही स्थिति रही तो धान का उत्पादन प्रभावित होगा।

-डीपीएस कंवर
उप संचालक कृषि

ट्रैफिक जवानों को प्रतिदिन कई घंटे खुले आसमान के नीचे खड़े रहकर यातायात नियंत्रित करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में जवानों को एसी वाले हेलमेट देने की तैयारी चल रही है।



ट्रैफिक जवानों के लिए एसी वाले हेलमेट का ट्रायल

रमन हलवाई **शेष पेज 6 पर**

रायपुर में शनिवार को उसका ट्रायल शुरू किया गया। यह तकनीक न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ा सकती है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि ट्रायल सफल रहता है तो भविष्य में अधिक संख्या में ट्रैफिक जवानों को ऐसे हेलमेट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पुलिस विभाग का मानना है कि बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने से जवानों की कार्यकुशलता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी। विवेक शुक्ला, एडीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि एक कंपनी द्वारा कुछ एसी हेलमेट ट्रायल के लिए उपलब्ध कराए हैं। भीषण गर्मी में द्यूटी करने वाले ट्रैफिक जवानों को राहत देने के उद्देश्य से इनका परीक्षण किया जा रहा है।



8 से 15 डिग्री तापमान कम कर सकता है हेलमेट

हेलमेट के ऊपरी हिस्से में एक छोटा बैटरी संचालित फैन और एयर-डक्ट सिस्टम लगा होता है। पीछे कमर या बेल्ट पर बैटरी पैक लगाया जाता है, जो फैन बाहर की हवा को खींचकर फिल्टर करता है और चेहरे व सिर की ओर भेजता है। कुछ मॉडलों में कूलिंग मॉड्यूल भी होता है, जो हवा का तापमान कुछ डिग्री कम कर देता है। एक बार चार्ज होने पर यह सामान्यतः 6 से 8 घंटे तक काम करता है। कंपनियों के बगों और पुलिस ट्रायल रिपोर्टों के अनुसार यह सिर के आसपास के तापमान को लगभग 8 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम महसूस करा सकता है, जिससे हीट स्ट्रेस और लू का खतरा घटता है।

रेस्क्यू टीम सदस्य सुनील ने किया चौकाने वाला दावा

केतन का सिर कुचला मिला, शांत थी सिया

एग्जेंसी **शेष पेज 6 पर**

केतन मर्डर केस में हर रोज नए-नए दावे सामने आ रहे हैं। केतन की रेस्क्यू करने वाली टीम के सदस्य सुनील गायकवाड़ ने दावा किया है कि केतन की खोपड़ी कुचली हुई थी, उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं और हाथ-पैर भी कई जगह चोट थीं। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद बाकी लोग मदद के लिए चिल्ला रहा थे, लोग रो रहे थे लेकिन सिया गोयल शांत खड़ी थी। गायकवाड़ ने बताया कि शव को जंगल के रास्ते बाहर लाया गया। 18 जून की सुबह 10:30 बजे घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी। रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर 12:30 तक चला और करीब 1:30 बजे शव एंबुलेंस में पहुंचाया गया था।

सगाई तोड़ने से आसान था खाई में धकेलना

लोहागढ़ फोटो मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिया गोयल ने उन्हें बताया कि उसका मानना था कि केतन अगवालों को लोहागढ़ फोटो में एक खाई में धकेलना, अपने परिवार का सामना करने और सगाई तोड़ने से ज्यादा आसान था। पुलिस ने कहा कि वे चल रही जांच के हिस्से के तौर पर बयान को वॉरिफाई कर रहे हैं।



केतन

सिया

केतन

सिया के माता-पिता और भाई से पूछताछ

महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के 25-वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अगवालों की कथित हत्या के मामले में सह-आरोपी सिया गोयल के माता-पिता और भाई को पूछताछ के लिए शनिवार को लोनावला (वार्मिंग) थाने तलब किया। सिया के माता-पिता (प्रवीण और पूजा गोयल) तथा उसके भाई सहित शनिवार सुबह पुलिस थाने पहुंचे। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को साहिल से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिसके बाद शाम को उसे जाने की अनुमति दे दी गई। **शेष पेज 6 पर**

31 मई से चल रही थी प्लानिंग

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने आखिरकार कामयाब होने से पहले कई कोशिशें कीं। 31 मई को सिया गोयल कथित तौर पर केतन अगवालों के साथ लोहागढ़ किले गई और विष् काट रिज के पास एक सुनसान जगह की पहचान की, जहां क्राइम किया जा सकता था। 4 जून के लिए एक और ट्रिप प्लान किया गया था लेकिन केतन अगवालों की मां के एतराज करने के बाद कैसल कर दिया गया। **शेष पेज 6 पर**

www.rungta.ac.in

Start Your Journey to a Rewarding Healthcare Career

Learn | Innovate | Impact Lives

SCHOOL OF LIFE SCIENCES

- B.Sc Biotechnology (Zoology / Botany) | (3 Years)
- B.Sc Forensic Science (3 Years)
- B.Sc. (Hons) Cosmetic Science (4Years)
- M.Sc Biotechnology | Forensic Science (2 Years)
- Diploma in Forensic Science (1 Year)
- Master in Public Health (2 Years)

SCHOOL OF PHARMACY

- B.Pharmacy (4 Years | PCI Approved)
- B.Pharmacy (Lateral) (3 Years | PCI Approved)
- D.Pharmacy (2 Years | PCI Approved)
- M.Pharmacy (Pharmaceutics | Pharmacology | Pharmaceutical Chemistry) (2 Years)
- B.Pharmacy Practice (2 Years | PCI Approved)

Industry Certifications

Modern Laboratories

Experienced Faculty

Placement Assistance

Backed by Industry-Ready Certifications

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Imperial College London

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

UNIVERSITY OF TORONTO

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Duke UNIVERSITY

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

NOVARTIS

UC San Diego

Bhilai Campus: Rungta R1 Educational Campus, Kohka-Kurud Road
Raipur City Office: Shop No. FF-1 & FF-2, First Floor, Shyam Plaza, Pandri

9016 11 3333
8880 48 8870

RCP
INFRA TECH PVT. LTD.

VIP CITY
A City in The City

VIP
Familia

3 BHK

STARTS FROM 1694 SQFT (157.43 SQMT)

2 BHK

STARTS FROM 1444 SQFT (134.2 SQMT)

AND
COMMERCIAL
SHOPS

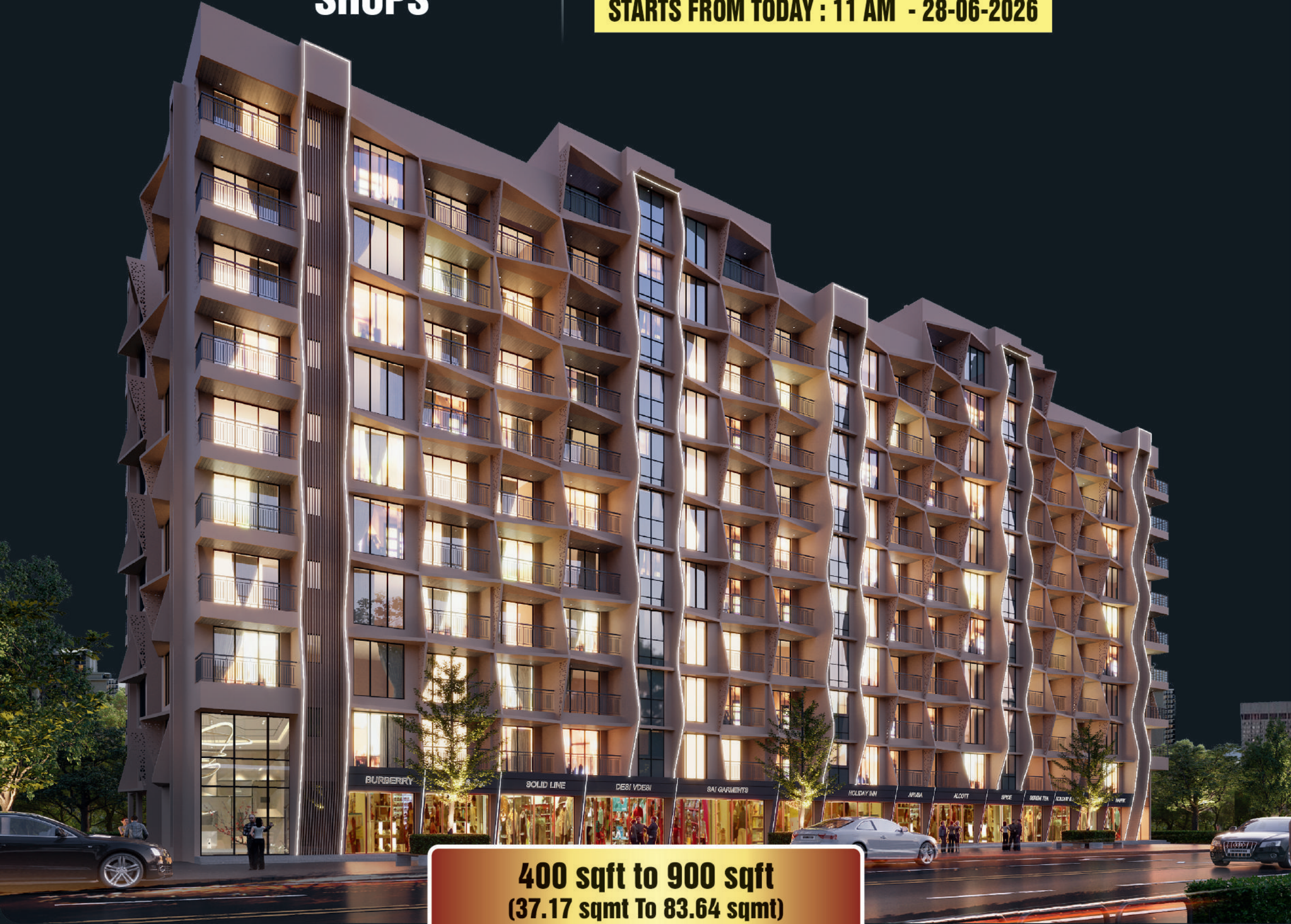
@ ~~2699/-~~ PER SQFT.

@ ~~3000/-~~ PER SQFT.

@ ~~3300/-~~ PER SQFT.

ONLY 10
SPECIFIC
FLATS

STARTS FROM TODAY : 11 AM - 28-06-2026



400 sqft to 900 sqft
(37.17 sqmt To 83.64 sqmt)
Commercial Shops & Offices

CALL-812 000 8290



ALSO KNOWN AS VIP FAMILY HEIGHTS
Member of: **CREDAI**
CHHATTISGARH
RERA REGISTERED PROJECT :
(VIP FAMILIA) RERA NO.: PCGRERA160524001777
www.rera.cgstate.gov.in

A PROJECT BY
RCP INFRA TECH PVT. LTD.
SADDU-URKURA ROAD, RING ROAD NO. 3, RAIPUR (C.G.)
EMAIL : RCPINFRA TECH.VIP@GMAIL.COM, WEBSITE : WWW.RCPINFRA.CO.IN

SCAN THIS QR
CODE TO FIND US
GOOGLE MAPS



Follow us on :



फायनेंस
उपलब्ध



Follow us on : [f/vipcityrpr](#) [@vipcityrpr](#)



बेफिक्र बच्चे

बेफिक्र बच्चे, चिंतित युवा और बुजुर्ग, बेदखली के डर से नहीं जले चूल्हे

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

राजधानी से लगे नकदी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए 77 परिवारों को 48 घंटे के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस मिला है। प्रशासन इसे राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रहा है, वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं, कई के

विधायकों के लिए उजड़ रही 77 परिवारों की दुनिया, 48 घंटे का नोटिस, चौपाल पर चिंता और बच्चों की बेफिक्र मुस्कान

पास सरकारी योजनाओं के तहत बने मकान हैं और पीढ़ियां यहीं बड़ी हुई हैं। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन गांव में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि घर टूटे तो इन परिवारों की अगली सुबह कहाँ होगी? प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी है, उस

गमगीन युवा, चिंतित बुजुर्ग

कुछ दूर घरों के बाहर बैठे युवा नजर आए। उनके बीच बातचीत कम और चिंता ज्यादा है। उनके सामने रोजी-रोटी, परिवार और भविष्य के सवाल हैं। कोई मोबाइल पर दस्तावेज देख रहा है, कोई राजस्व रिकॉर्ड की चर्चा कर रहा है। गांव के बुजुर्गों के चेहरे सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई देते हैं। जिन हाथों ने दशकों पहले यहां घर बसाए थे, वे अब उसी जमीन से बिछड़ने की आशंका में खामोश बैठे हैं।



चिंतित युवा

समाचार ही नहीं, विचार भी

बुजमोहन बोले- बिना पुनर्वास किसी को नहीं करेंगे बेघर

प्रभावित ग्रामीणों ने सांसद बुजमोहन अग्रवाल से मेट की। ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस और उसके बाद उत्पन्न स्थिति से सांसद को अवगत कराया। इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए सांसद बुजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कार्यों के लिए किसी



विधायक कॉलोनी के लिए चुनी गई जमीन

नकदी गांव की भौगोलिक स्थिति इसे महत्वपूर्ण बनाती है। यह क्षेत्र एयरपोर्ट, पुराना रायपुर और नवा रायपुर के बीच संपर्क का प्रमुख बिंदु है। इसी वजह से यहां विधायक कॉलोनी विकसित करने का प्रस्ताव है। ग्रामीणों का तर्क है कि नवा रायपुर में सरकार के पास पहले से पर्याप्त भूमि और कई खाली भूखंड उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक परिस्तर विकसित करना है तो उसके लिए ऐसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे वर्षों से बसे परिवारों को विस्थापन का सामना न करना पड़े।

चूल्हे नहीं जले, चौपाल पर बीता दिन

नोटिस मिलने के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया है। कई परिवारों में शनिवार को चूल्हे तक नहीं जले। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सुबह से चौपाल पर जुटे रहे। लोगों को आशंका थी कि कहीं नोटिस के अगले ही दिन कार्रवाई शुरू न हो जाए। दोपहर बाद सामना न करना पड़े।



खबर संक्षेप

आरोग्य सेतु ऐप का नया संस्करण कल नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा सोमवार को पुनर्निर्मित आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत करेंगे। यह ऐप मूल रूप से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया था। अब यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी को संपूर्ण रूप से प्रबंधित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

लॉज-कोचिंग सेंटर समेत 4 संस्थान सील

बिलासपुर। जिला प्रशासन की ओर से फायर सेफ्टी मानकों की जांच के लिए गठित की गई संयुक्त टीम द्वारा शनिवार को एक के बाद एक शहर के कई संस्थाओं में ताबड़तोड़ जांच और कार्रवाई की गई। यह संयुक्त टीम सबसे पहले मंगला चौक से उसलापुर क्षेत्र तक स्थित दिल्ली आईएएस कॉलेज, शारदा लाइब्रेरी, ऑफिसर्स लाइब्रेरी, बिलासा लाइब्रेरी, शिवाय लाइब्रेरी, उड़ान आईएएस, 24x7 लाइब्रेरी एवं भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जांच की गई। करीब पांच घंटे तक जांच व कार्रवाई चली।

गुलमर्ग में विस्फोट एक की मौत

गुलमर्ग। उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग के फॉरवर्ड एरिया में आशा पोस्ट के पास आज एक विस्फोट होने की घटना सामने आई। इस हादसे में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। यह शेल कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इलाके में गिरा हुआ था, जो आज अचानक फट गया।



सेशेल्स पहुंचे पीएम मोदी

दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए से मिले मोदी

एजेंसी ►► विक्टोरिया (सेशेल्स)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हरिंमनी के साथ सेशेल्स राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले जीवित स्थलीय जीव 'जोनाथन' से मिले। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति हरिंमनी के साथ पौधरोपण समारोह में भी हिस्सा लिया जो जैव-विविधता संरक्षण तथा पर्यावरण सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंग्रेजों के जमाने का 'जोनाथन'

बता दें, जोनाथन अल्ट्राडा जायंट कछुआ है। उसकी उम्र करीब 194 साल बताई जाती है। यह विशाल कछुआ उप-प्रजाति का जोनाथन जेम्सटाउन स्थित नेशनल बोटनिकल गार्डन में रहता है। माना जाता है कि उसका जन्म 1832 के आसपास हुआ था, हालांकि की इसके बारे में कोई स्टैंक जानकारी नहीं है।

राम मंदिर चढ़ावा गबन : ट्रस्ट की अहम बैठक 11 जुलाई को, चंपत की जगह कौन, होगा फैसला

राम मंदिर में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर अब सीईओ की नियुक्ति!

हरिभूमि न्यूज ►► अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरि ने एक बयान में कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इस मामले में निर्णय लेगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर दान के गबन से जुड़े विवाद की नै ति क जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के साथ-साथ विश्व हिंदू परिषद, जिसके राय उपाध्यक्ष हैं, ने भी इस खबर की पुष्टि की। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राय और अन्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा, दोनों के इस्तीफे के बारे में गिरि का पत्र पोस्ट किया, हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इस्तीफों पर फैसला

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव के इस्तीफे के बाद उनकी जगह कौन लेगा? यह सवाल उठने लगा है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर व्यवस्था को लागू किए जाने की चर्चा चल रही है। सीईओ की नियुक्ति से मंदिर में आने वाले पैसों और दान की राशि का उचित प्रबंधन किया जाएगा।

अनिल की जगह कृष्ण मोहन की चर्चा

अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद चर्चाएं तेज हो गईं कि उनकी जगह कृष्ण मोहन ले सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे बाद उनका दायित्व कृष्ण मोहन को सौंपे जाने की सुगबुगाहट तेज है। चढ़ावे चोरी मामले में आरोपियों पर एफआईआर में वादी बनने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण गोपाल का नाम सुर्खियों में आ गया। गुरुवार देर शाम से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके इतिहास को खोजा जाने लगा। इतनी प्रसिद्धि उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनते समय नहीं मिली थी।



एसआईटी जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं

चांदी की ईंटें और आभूषण सुरक्षित

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि ने कहा कि हम उन मक्तों को आश्वस्त करते हैं, जिन्होंने चांदी की ईंटें और सोने-चांदी के आभूषण प्रभु श्रीराम की सेवा में अर्पण किए हैं। वे सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को कड़ा दंड मिले, इसका आग्रह करेंगे।

आरोपियों की संपत्ति जब्त कर चैरिटी में दी जाए : सोनू सूद

मिलाई। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित हेरफेर के मामले पर अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने कहा है कि श्रद्धालु अपनी आस्था, मेहनत की कमाई, बचत और वेतन का हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग करता है तो वह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास के साथ विश्वासघात है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर उसे मंदिर की चैरिटी, जनसेवा और जरूरतमंदों की मदद के कार्यों में लगाया जाना चाहिए। मिलाई में आयोजित सूद चैरिटी फाउंडेशन के एनएल मीट कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सोनू सूद ने पत्रकारों से चर्चा में यह बातें कही।

हीरा खनन की तैयारी, बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में बड़े व्यास की ड्रिलिंग को एनसीएल बोर्ड की मंजूरी

हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज



छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक : सौरभ

बैठक में यह भी देहराया गया कि सभी परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निदेशक सौरभ सिंह ने कहा, खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बहु-खनिज विकास की दिशा आगे बढ़ी

एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड (51 प्रतिशत) तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (49 प्रतिशत) का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी अब तक लौह अयस्क परियोजनाओं पर केंद्रित रही है, लेकिन बलौदा-बेलमुंडी में प्राकृतिक हीरों की पुष्टि के बाद यह बहु-खनिज विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एनसीएल की भूकंप के लिहाज से कांपी सैटलिंग, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग के माध्यम से किन्नरलाइट पाइप की पहचान की गई। इसके

बालको मेडिकल सेंटर
मध्यभारत का अत्याधुनिक व विश्वसनीय कैंसर हॉस्पिटल
NABH व NABL से मान्यता प्राप्त

आयुष्यान भारत योजना से निःशुल्क ईलाज एवं सभी PSUs व बीमा कंपनियों से अनुबंधित

- सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी (रोबोटिक/लेपोस्कोपिक),
- चेट, स्क्वेड स्कैन, MDT, LDT थेरेपी
- कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी
- रक्त-सम्बन्धी सभी बीमारियाँ एवं ब्लड मेरो ट्रांसप्लांट
- आधुनिक रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी एवं बोलड सेंटर
- अत्याधुनिक टू-बीम लिनक एवं हैल्सीऑन मशीन द्वारा रेडिएशन थेरेपी व ब्रैकिथेरेपी की सुविधा

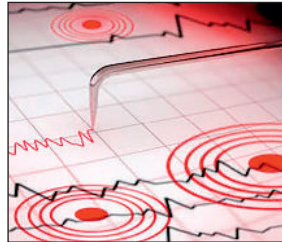
बीएमसी सिटी कैंसर डेकेयर - कलर्स मॉल के बाजू, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) ☎ 9201966330
मेन हॉस्पिटल: सेक्टर 36, नया रायपुर, (छ.ग.) ☎ 8282823333/4444

वेनेजुएला के बाद कई देशों में डोली धरती

अफगानिस्तान में भूकंप, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में झटके

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में शनिवार शाम 6 बजकर 4 मिनट पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से अत्यधिक गहराई में होने के कारण इसके झटके पाकिस्तान, भारत के उत्तरी हिस्से, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत कई देशों में महसूस किए गए। दिल्ली-एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।



हिमाचल में पहले आया था भूकंप

इससे पहले, भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भारतीय समयानुसार सुबह 11:38 बजे आए इस भूकंप की गहराई धरती की सतह से महज 5 किलोमीटर की गहराई में थी। इसका केंद्र धर्मशाला से करीब 22 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में, भूकंपीय रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में स्थित था।

घर-दफतर से बाहर आए लोग

जम्मू-कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए और लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर सड़कों और खुली जगहों की ओर भागे। जम्मू-कश्मीर भी भूकंप के लिहाज से कांपी संवेदनशील है। यहां समय-समय पर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंपीय झटके महसूस होते रहते हैं।

अमूल मिल्क के संग...

कीजिए चैम्पियन्स का हौसला बुलंद!

साथ हो अमूल मिल्क का ताजगी भरा स्वाद तो बदल जाएगा मैच देखने का अंदाज!

इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आनंद लीजिए आपके पसंदीदा अमूल मिल्क के साथ और अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाइए।

ARGENTINA DEFENDING CHAMPIONS

Amul x

Official Regional Sponsor

200mL 180mL 1L 500mL

अमूल मिल्क. हमेशा फ़ेश.

अमूल

हमारे शहरों में बढ़ती जनसंख्या और उसके अनुरूप अनियोजित भवन निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से जानलेवा साबित हो रहे हैं। आवासीय इलाकों में बिना सोचे-समझे व्यावसायिक गतिविधियां और कारखाने खोल दिए जाते हैं। ऐसे में जब कभी आग लगती है तो संकरी गलियों के कारण दमकल विभाग की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं। ऐसे में हादसा अनगिनत जानों को लील लेता है। प्रशासन द्वारा निर्धारित भवन निर्माण के नियम कोई ठकावट नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए बेहद जरूरी सुरक्षा कवच हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अवैध निर्माण लालची बिल्डरों और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के गठजोड़ से फलते-फूलते हैं। बिल्डर सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करते हैं, अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और खरीदार अंत में फंसता है। छोटे शहरों में स्थिति और भी बदतर है। यहां नगर पालिकाएं संसाधनों की कमी और स्थानीय दबाव के आगे घुटने टेक देती हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे और सुरक्षित भवन निर्माण की दिशा में तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए तो भविष्य में आगजनी की घटना अथवा आने वाला एक छोटा सा भूकंप भी हमारे विकास के सभी दावों को मलबे में बदल देगा। *इन्हीं हालातों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

अनियोजित शहरीकरण से हादसों को निमंत्रण



विश्लेषण

डॉ. चंद्र त्रिखा

वरिष्ठ स्तंभकार

विकास की इस तेज भागदौड़ में हम यह बुनियादी बात भूल जाते हैं कि शहर केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे के बेजान ढांचे नहीं हैं; बल्कि ये एक जीती-जागती व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था को सही ढंग से चलने और सुरक्षित रहने के लिए एक दूरदर्शी योजना की बहुत जरूरत होती है। आज हमारे शहर बिना किसी सही योजना के जिस तरह से फैल रहे हैं, वह किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी नाकामी 'भवन निर्माण के नियमों' की अनदेखी के रूप में सामने आती है, जो हमारे शहरों को एक सुलगते ज्वालामुखी में बदल रही है। भवन निर्माण के नियम किसी भी सुनियोजित शहर की रीढ़ होते हैं। ये वे कानूनी और तकनीकी दिशा-निर्देश हैं जो यह पक्का करते हैं कि कोई भी इमारत रहने वालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। इन नियमों में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं। जैसे कि इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली खाली जगह, जमीन के अनुपात में निर्माण की अधिकतम सीमा, आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम, भूकंप सहने की क्षमता, और आपात स्थिति में बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते। इसके पीछे का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि पड़ोसियों को भी पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। जब शहरों का फैलाव बिना किसी पक्की योजना के, रातों-रात मनमाने तरीके से होता है, तो सबसे पहले इन्हीं नियमों की बलि चढ़ाई जाती है।

नियमों की हो रही अनदेखी

ज्यादा मुनाफे की चाहत और जगह की कमी के नाम पर निर्माण करने वाले ठेकेदार और खुद भवन मालिक भी इन नियमों को ताक पर रख देते हैं। नतीजा यह होता है कि तंग गलियों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, जिनमें न तो हवा आने का कोई रास्ता होता है और न ही धूप का। इस अनदेखी का सीधा असर उन खोफनाक हादसों के रूप में सामने आता है, जो अब हमारे शहरों की रोजमर्रा की कहानी बन चुके हैं। बहुमंजिला इमारतों में भयानक आग लगने या उनके भरभरा कर गिर जाने की दर्दनाक खबरें अब आम हो गईं



खास बातें

- भवन निर्माण के नियम हमारे और परिवार के जीवन की सुरक्षा की गारंटी
- संकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं।
- नगर निगम और जमीन माफियाओं का भ्रष्ट गठजोड़ असली जिम्मेदार
- शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए नियमों का पालन ही एकमात्र विकल्प

हैं। आवासीय इलाकों में बिना सोचे-समझे व्यावसायिक गतिविधियां और कारखाने खोल दिए जाते हैं। ऐसे में जब कभी आग लगती है, तो संकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं। इन इमारतों में संकट के समय बाहर निकलने के रास्ते या तो होते ही नहीं, या उन पर फालतू सामान रखकर रास्ता रोक दिया जाता है।

दम घुटने से ज्यादा मौतें

हवा के आने-जाने का सही रास्ता न होने के कारण आग लगने पर लोग लपटों से कम, और जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण ज्यादा जान गंवाते हैं। इसी तरह, कमजोर नींव, घटिया निर्माण सामग्री और बिना अनुमति के बनाई गई अतिरिक्त मंजिलों के कारण कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। जब इमारत बनाने से पहले मिट्टी की जांच और ढांचे की मजबूती परखने जैसे जरूरी कामों को नजरअंदाज किया जाता है, तो भूकंप का एक हल्का झटका या तेज बारिश भी भारी तबाही ला सकती है। बिना

योजना के बसाए गए शहर जलभराव जैसी गंभीर मुसीबतों का भी मुख्य कारण हैं। भवन निर्माण नियमों में पानी की निकासी और बारिश के पानी को सहेजने के सख्त नियम होते हैं। अवैध निर्माण की होड़ में प्राकृतिक जल स्रोतों, नालों और तालाबों को मिट्टी से भरकर वहां ईंट-पत्थर के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं।

जमा पानी की निकासी नहीं

इसका नतीजा यह होता है कि थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। पानी के निकलने का कोई रास्ता न बचने के कारण इमारतों के निचले हिस्सों में पानी भरने से होने वाली मौतें अब एक डरावनी सच्चाई अनुमति के बनाई गई अतिरिक्त मंजिलों के कारण कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। जब इमारत बनाने से पहले मिट्टी की जांच और ढांचे की मजबूती परखने जैसे जरूरी कामों को नजरअंदाज किया जाता है, तो भूकंप का एक हल्का झटका या तेज बारिश भी भारी तबाही ला सकती है। बिना

खुलेआम अवैध निर्माण होता रहता है और जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी रहती है। रिश्तत और पहुंच के दम पर नियमों के खिलाफ बनी इमारतों को भी निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र आसानी से मिल जाते हैं। सस्ते घर के लालच में लोग ऐसी इमारतों में अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा देते हैं, जो कभी भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। अब वह समय आ गया है कि बिना योजना के बढ़ते शहरीकरण और नियमों की अनदेखी पर गंभीरता से विचार किया जाए। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को अपनी जिम्मेदारी सख्ती से समझनी और निभानी होगी। नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

अवैध निर्माण वैध करना गलत

जुर्माना लेकर अवैध निर्माण को वैध कर देने की गलत परंपरा को तुरंत बंद करना होगा। हवाई सर्वेक्षण और उपग्रह से प्राप्त चित्रों जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अवैध निर्माणों को शुरूआत में ही रोका जाना चाहिए। घर खरीदते या बनाते समय यह जांचना हर नागरिक का भी फर्ज है कि वह इमारत सभी कानूनी और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हो। यदि बिना सोचे-समझे हो रहे शहरीकरण पर नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ, तो ये बेतरतीब जंगल इसी तरह दर्दनाक हादसों को न्योता देते रहेंगे।

शहरीकरण की भूख से बर्बाद हो रहा मानव जीवन



हादसा

योगेश कुमार सोनी

वरिष्ठ पत्रकार

बदती जनसंख्या के कारण शहरी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव और हादसों का सबसे बड़ा कारण अनियोजित और अनियंत्रित शहरीकरण है, जिसके चलते बुनियादी ढांचा जिसमें सड़कें, सौर, बिजली शामिल हैं- यह सब चरमरा जाता है। इससे भीड़भाड़, यातायात के दबाव और असुरक्षित निर्माण जैसे हादसे होते हैं। सीमित सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ और पैदल यात्रियों के मिश्रण से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। बुनियादी ढांचे के अभाव में लोग अवैध, अनियोजित और कमजोर इमारतों में रहने को मजबूर होते हैं, जो दहने या आग लगने जैसे हादसों का कारण बनती हैं। क्षमता से अधिक भार के कारण बिजली के शॉर्ट-सर्किट और आग लगने जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। जनसंख्या बढ़ने और कंक्रीट के जंगल बनने से बारिश के पानी की सही निकासी नहीं होती, जिससे सड़कों पर जलभराव, गड्ढे और कंटेनर फैलने के घातक हादसे होते हैं।

यदि महानगरों की बात करें तो वह नब्बे प्रतिशत से अधिक अवैध रूप से इमारतें बनती हैं। चूँकि बिना नक्शे की खिलिंडिंग बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, जिसके चलते लोग नगर निगम के अधिकारियों को रिश्ता देकर बिना नक्शे की इमारत बना लेते हैं। लोगों की हदसय यहां तक भी नहीं रुकती- पार्किंग के साथ चार पलोर तक बना सकते हैं, लेकिन कुछ पांच से सात पलोर तक बना लेते हैं और कई लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। जब हादसा होता है तो कई लोग बेमौत मारे जाते हैं। नियम को अनदेखी करना जैसे लोगों की फितरत में शामिल हो गया। अब भवन निर्माण उपनियम आया तो लोगों के घर टूट रहे हैं जिससे अब लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें लोगों की भी गलती नहीं मानी जा सकती, चूँकि जैसा सिस्टम था, वह उनके अनुसार ही चल रहा थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब सत्ता बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है- मरना अंत में जनता का ही होता है। नक्शे व संबंधित डॉक्यूमेंट में यह स्पष्ट होता है कि इन खसरो पर किसी भी भवन या भूखंड का मानचित्र प्राधिकरण में रजिस्ट्रार नहीं हो सकता। यहां बने निर्माण पूरी तरह अवैध हैं, इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सौर, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लोगों से कहा है कि किसी भी जमीन या भवन की खरीद-बिक्री से पहले उसकी स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

बलजिंदर इसके बिल्डर इटल्ले से इमारत बना कर बेचते हैं और आश्चर्य की बात कि लोग खरीदते भी हैं। सीलिंग के बाद भी यहां बिजली पानी के मीटर तक लगा जाते हैं। यदि हम हिन्दुस्तान के परिदृश्य में चर्चा करें तो हमारे यहां जनसंख्या का बेहद तेजी से बढ़ना जारी है तो उस आधार पर सरकारों को जनता के लिए जगह की व्यवस्था करनी होती है। इसके चलते जंगल का पर्यावरण बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। देश की तरक्की व जनता की जरूरत के लिए ऐसे मुद्दों की गंभीरता न समझना मानव जीवन पर ही भारी पड़ रहा है। मनुष्य की शहरीकरण की भूख ने इतनी हानि पहुंचा दी कि उसको यह मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब काल के गर्भ में प्रवेश कर गया। यदि महानगरों की जीवनशैली व यापन की चर्चा करें तो यहां पिछले दो दशकों कम आयु में होने वाली मौतों के आंकड़ों ने चौंका दिया। मनुष्य की आयु का घटना लगातार जारी है। इंसान की उम्र करीब सौ वर्ष होती थी, लेकिन आज के दौर में साठ साल पर आकर सीमित रह गई। वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार हो रही आपदाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेहद अधिक इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया है। उनका मानना है कि आज स्थिति के आधार पर हमारी धरती अपने भार से कहीं अधिक भार वहन कर रही है। अगर यही हाल रहा तो अगले दशकभर में धरती रहने लायक नहीं बचेगी, लेकिन मनुष्य आज भी सही राह पर चले तो वो अपना भविष्य सुधार सकता है। हर रोज न जाने कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। वैश्विक सरकारों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में भी इसको बेहद गंभीर मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन कुछ देर ही जागरूक होकर फिर पुराने ढंग पर आ जाते हैं, जिससे हम सही दिशा पर नहीं आ पा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार ऐसे मामलों में कड़ा बलट पॉसिबिलिटी है इसके प्रति गंभीर भी रहती हैं। इसके लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर विभाग कार्यरत भी हैं, लेकिन हम उतनी सज्जीबगी से इस बात की गंभीरता नहीं समझ पा रहे, जितने की जरूरत है। सरकार को कोई ऐसा नियम निकालना चाहिए, जिससे शहरों में नियम-कानून के साथ इमारत बनें। यदि किसी जगह आग लग जाती है तो शहरों की छोटी तो छोड़ो, बड़ी गलियों तक में एंबुलेंस नहीं जा पाती, चूँकि लोगों ने सड़कों को घेरा हुआ है।

देश की तरक्की व जनता की जरूरत के लिए ऐसे मुद्दों की गंभीरता न समझना मानव जीवन पर ही भारी पड़ रहा है। शहरीकरण की भूख ने इतनी हानि पहुंचा दी कि मनुष्य को यह मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब काल के गर्भ में प्रवेश कर गया।

भ्रष्ट नियामक और वास्तु का क्रेज



विरोधाभास

विवेक शुक्ला

वरिष्ठ पत्रकार

भारत में छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक, भवन निर्माण नियमों का पालन एक सपना बनकर रह गया है। जहां एक ओर नियामक संस्थाएं कानून की रखवाली का दायित्व निभाने के बजाय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी वास्तु शास्त्र के नाम पर 'परिपूर्णा' घर बनाने की होड़ में लगा हुआ है। यह विरोधाभास न केवल शहरी नियोजन को चुनौती दे रहा है, बल्कि सुरक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के सवाल भी खड़े कर रहा है। भारतीय शहरों में अनधिकृत निर्माण की समस्या कोई नई नहीं है। हर बड़े और छोटे शहर में यही कहानी दोहराई जाती है। भवन निर्माण नियम भूतल क्षेत्र अनुपात, पीछे हटाव, ऊंचाई सीमा, वाहन पार्किंग स्थान, अग्नि सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों को तय करते हैं, लेकिन इनका उल्लंघन आम बात है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध निर्माण बिल्डर और सरकारी अधिकारों के गठजोड़ से फलते-फूलते हैं। बिल्डर सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करते हैं, अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और खरीदार अंत में फंसता है। छोटे शहरों में स्थिति और बदतर है। यहां नगर पालिकाएं संसाधनों की कमी और स्थानीय दबाव के आगे घुटने टेक देती हैं। एक साधारण प्लॉट पर मंजूरी से दोगुनी मंजिलें चढ़ जाती हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से बड़े हादसे होते हैं। बड़े शहरों में ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में प्रवेश कक्ष और तहखाने को व्यावसायिक स्थान में बदल दिया जाता है। कई कॉलोनियों में यह स्थिति है, जहां नियमों की अनदेखी आम हो गई है। नियामक संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों बनीं? कारण स्पष्ट हैं- राजनीतिक दखल, कमीशन की संस्कृति और जवाबदेही का अभाव। भवन अनुमोदन प्रक्रिया में स्वयं प्रमाणन का चलन बढ़ा है, जहां इंजीनियर का प्रमाण पत्र ही

काफी माना जाता है। स्थल निरीक्षण नाममात्र का होता है। पारदर्शिता की कमी और डिजिटल निगरानी का अभाव समस्या को बढ़ाता है। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि शहरी नियोजन में रिश्ताखोरी की पिरामिड संरचना काम करती है, निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक। इस बीच, वास्तु शास्त्र का क्रेज आसमान छू रहा है। लोग नए घर या कार्यालय बनाते समय दिशाओं, रंगों, सामग्री और 'ऊर्जा प्रवाह' का ख्याल रखने लगे हैं। वास्तु सलाहकारों की फीस लाखों में पहुंच गई है। देश के विभिन्न महानगरों में 'वास्तु अनुरूप' संपत्तियों की मांग बढ़ी है। बिल्डर विपणन में इसे अनोखी

अतिरिक्त बालकनी या कमरे जोड़े जा रहे हैं, जो इमारत की मजबूती को कमजोर कर देते हैं। इससे शहरों की सौंदर्यता बिगड़ रही है और यातायात जाम बढ़ रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह हानिकारक है, क्योंकि हरे-भरे स्थान धिर रहे हैं। समाधान क्या है? सबसे पहले, भवन निर्माण नियमों को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाना होगा।

भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन सर्वेक्षण और ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली लागू करें। भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, आपराधिक दायित्व और तीसरी पक्ष की जांच जरूरी है। वास्तु को वैज्ञानिक दृष्टि से बढ़ावा दें-इसे सतत



आज कई परिवार घर बनाते समय वास्तु विशेषज्ञ बुलाते हैं, लेकिन निर्माण नियमों की अनदेखी करते हैं। अगर हम नियमों का पालन करें और वास्तु को समझदारी से अपनाएं, तो ही सुंदर और सुरक्षित शहर बना पाएंगे। साफ है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जागरूकता से ही यह समस्या हल हो सकती है।

विशेषता बना रहे हैं- 'उत्तर मुखी', 'सकारात्मक ऊर्जा' वाले प्लैट। आज कई परिवार घर खरीदते या बनाते समय वास्तु विशेषज्ञ बुलाते हैं, लेकिन निर्माण नियमों की अनदेखी करते हैं। नतीजा? भूकंप या आग में जान-माल का नुकसान। वास्तु अच्छा है-यह प्राचीन भारतीय विज्ञान पर्यावरण और मनोविज्ञान को जोड़ता है-लेकिन जब यह भ्रष्ट निर्माणों को सही ठहराने का बहाना बन जाए, तो समस्या गहरी हो जाती है। बिल्डर 'वास्तु अनुरूप' कहकर अवैध विस्तार बेचते हैं, जबकि अग्नि निकास या संरचनात्मक सुरक्षा की परवाह नहीं करते। देश के कई इलाकों में वास्तु के नाम पर

वास्तुकला का हिस्सा बनाएं, न कि अंधविश्वास का, लेकिन अंधविश्वास और नियमों की अनदेखी खतरनाक है। देश के प्रख्यात वास्तुकार उमजवेल उपाध्याय कहते हैं कि सकारों स्मार्ट शहर, अमृत ध्यान केंद्रित करें। जन जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि खरीदार नियम जांचें। अगर हम नियमों का पालन करें और वास्तु को समझदारी से अपनाएं, तो ही स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित शहर बना पाएंगे। साफ है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जागरूकता से ही यह समस्या हल हो सकती है।

बिल्डिंग बायलॉज का कड़ाई से हो पालन



व्यवस्था

डॉ. विजेंद्र कुमार

स्वतंत्र स्तंभकार

विकास की अत्यंत तेज रफ्तार ने हमारे शहरों को आसमान छूती ऊंची इमारतों और कंक्रीट के विशाल जंगलों में बदल दिया है। दूर से देखने पर ये शहर भले ही बहुत आधुनिक और प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन इनकी नींव में एक ऐसी भयंकर लापरवाही छिपी है, जो किसी भी पल एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। आज हमारे शहर भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो चुके हैं।

विडंबना यह है कि इन शहरों में भूकंप से बचाव करने वाली तकनीक और इससे जुड़ी संस्थाओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी नाजुक और चिंताजनक हो चुकी है कि एक छोटा या मध्यम गति का भूकंप भी हमारे शहरों में बहुत बड़े हादसों का कारण बन सकता है। ऐसे में 'भवन निर्माण के नियमों' का वास्तविक महत्व और उनका पूरी कड़ाई से पालन करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से उत्तर भारत, हिमालय के आसपास के पहाड़ी इलाके और कई घनी आबादी वाले बड़े शहर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इन इलाकों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी और बिना किसी उचित योजना के हो रहे शहरीकरण ने खतरे को कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। शहरों में जगह की भारी कमी और ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में लोग संकरी गलियों के भीतर भी कई मंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं। इन इमारतों को बनाते समय न तो मिट्टी की मजबूती की ठीक से जांच की जाती है और न ही दो इमारतों के बीच आवश्यक दूरी छोड़ी जाती है। यह हमारी उस लापरवाह सोच का नतीजा है जो मुसीबत आने से पहले उसकी तैयारियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। किसी भी शहर के सुरक्षित, व्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए 'भवन निर्माण के नियम' बनाए जाते हैं। इन नियमों में मुख्य रूप से इमारत की ऊंचाई, नींव की

गहराई, इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता, हवा-रोशनी की उचित व्यवस्था, आपात स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते और भूकंप से बिचल के मापदंड तय होते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय जान और माल के नुकसान को कम करना है। हकीकत यह है कि ये महत्वपूर्ण नियम अक्सर केवल सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई के कारण इनकी खुलेआम अनदेखी होती है। नक्शे में जो डिजाइन कागजों पर दिखाया जाता है, असल निर्माण उससे बिल्कुल अलग होता है। कई बार ठेकेदार बिना



हर नई इमारत का निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से होना चाहिए, लेकिन आज भी आम आदमी इसे एक फालतू खर्च मानकर इससे बचने का प्रयास करता है। इसके अलावा, देश में ऐसे कुशल इंजीनियरों, राजमिस्त्रियों की भारी कमी है, जिन्हें इस तकनीक का सही और व्यावहारिक ज्ञान हो

किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए मनमाने तरीके से इमारतें तान देते हैं। भूकंप के खतरों की गंभीरता को देखते हुए हर नई इमारत का निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से होना चाहिए, लेकिन आज भी आम आदमी इसे एक फालतू खर्च मानता है और इससे बचने का हर संभव प्रयास करता है। इसके अलावा देश में ऐसे कुशल इंजीनियरों, राजमिस्त्रियों और निर्माण संस्थाओं की भारी कमी है, जिन्हें इस तकनीक का सही और व्यावहारिक ज्ञान हो। हमारे पास ऐसी संस्थाओं का भी घोर अभाव है जो पुरानी और कमजोर पड़ चुकी इमारतों को नई तकनीक के

हो जाते हैं और बचाव कार्य के लिए दमकल की गाड़ियों या एंबुलेंस का पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं जहां धरती का हल्का झटका भी हजारों जिंदगियों को मलबे में दबा सकता है। इस बड़े खतरे से निपटने के लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। इसके अलावा देश में ऐसे कुशल इंजीनियरों, राजमिस्त्रियों और निर्माण संस्थाओं की भारी कमी है, जिन्हें इस तकनीक का सही और व्यावहारिक ज्ञान हो। हमारे पास ऐसी संस्थाओं का भी घोर अभाव है जो पुरानी और कमजोर पड़ चुकी इमारतों को नई तकनीक के



कठिन समस्याएं अब न होंगी

क्यूक सच्ची सहेली में हैं **67** खास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां जो मुश्किल तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करें।

24x7 Helpline: 77106 44444 • www.sachisaheli.in



67 दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बना 'सच्ची सहेली' आयुर्वेदिक टॉनिक एवं टेबलेट्स

Helps in:

- कठिन दर्द
- चिड़चिड़ापन
- थकान
- कमजोरी
- कमर कटना
- इम्यूनिटी



वेनेजुएला में भूकंप के फिर लगे झटके

51 हजार से ज्यादा लापता, अब तक 920 मौतें, 3300 घायल

कराकस। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में लगातार आफत जारी है। 25 जून को आए दो भूकंप के बाद स्थानीय समयानुसार शुक्रवार दोपहर को एक और भूकंप आया। देश के उत्तरी तट के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। रेंजटर्स के मुताबिक, राजधानी कराकास और मारके में भी झटके महसूस किए गए। इधर, पिछले भूकंप के तीन दिन बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। 3360 से ज्यादा घायल हैं, जबकि 51,700 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई इलाकों में राहत टीमों की कमी के कारण लोग परिजन को ढूँढ़ने के लिए खुद मलबा हटा रहे हैं। कई परिवार हथौड़ों और दूसरे औजारों से इमारतों का मलबा हटाकर अपने परिजन की तलाश कर रहे हैं।



अगले 72 घंटे हैं अहम
राहत और बचावकर्मियों द्वारा युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए 42 से 72 घंटे बहुत अहम होते हैं। इस आपदा के बाद वेनेजुएला में अंतरराष्ट्रीय राहत और बचाव दल भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 243 लोगों को जिंदा बचाया गया है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।

खबर संक्षेप

गाजा पर मोदी सरकार क्यों है चुप : सोनिया



नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गाजा के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार की 'निरंतर चुप्पी' पर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि भारत को फलस्तीनियों के समर्थन में स्पष्ट और मुखर रुख अपनाया चाहिए तथा गाजा और वेस्ट बैंक में हो रही घटनाओं पर वैश्विक जनमत के अनुकूप प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गांधी ने एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लिखे लेख में संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि गाजा में बच्चों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ की मानवीय स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है।

स्टालिन को लगा झटका एमडीएमके ने छोड़ा साथ

चेन्नई। तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में स्टालिन की डीएमके को एक और झटका लगा है। एमडीएमके ने औपचारिक रूप से डीएमके के साथ अपना नौ साल पुराना गठबंधन समाप्त कर दिया है। हालांकि उसने सत्तारूढ़ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह नियमित पार्टी की आम सभा की बैठक में लिया गया। अपने प्रस्तावों में एमडीएमके ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार का स्वागत किया और उससे प्रमुख चुनावी वादों पर अडिग रहने का आग्रह किया। जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाए रखना और मेकेंदातु बांध परियोजना जैसे मुद्दों पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। प्रस्तावों में टीवीके गठबंधन में शामिल होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

मुहर्रम जुलूस में 14,900 जहरीले कैप्सूल बांटने पहुंचा, गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई ने एक शख्स को चूहे मारने वाले जहर से भरे 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति बायकुला के मुहर्रम जुलूस में कैप्सूल बांटने के लिए घूम रहा था। वह लोगों को बता रहा था कि यह हर



प्रकार के दर्द को जड़ से खत्म करने की दवा है। इसी जुलूस में एक

शख्स का पेट दर्द और उल्टी होने लगी। पूछताछ में शख्स ने बताया कि उसने एक व्यक्ति से कैप्सूल लेकर खाया था। इसके बाद पुलिस ने उस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी की पहचान फैयाज प्रेमजी के रूप में हुई है।

मिडिल ईस्ट में तनाव, ईरान ने भी किया बहरीन पर अटैक

युद्धविराम पर फिर मंडराया संकट, अमेरिका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों पर किए हमले

एजेसी ►► वाशिंगटन

अमेरिका ने ईरान पर शुक्रवार को करीब एक घंटे तक हमले किए। इस दौरान अमेरिकी सेना ने उसके मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीजफायर तोड़ा है और इसलिए उस ये जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिका ने यह कार्रवाई तब की है, जब तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कर्माश्रित कारगो शिप पर हमला किया था। हाल ही में दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में एक नाजुक समझौता हुआ था और इस हमले के बाद दोनों के बीच फिर से तनाव दिख रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 'हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा।' जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान ने युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने उसका पूरी तरह सम्मान किया। अगर समझौते (एमओयू) को लेकर किसी तरह का विवाद है तो बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। वेंस ने कहा, 'अगर किसी बात से दिक्कत है तो आपके पास फोन है। लेकिन अगर हिंसा करोगे तो हिंसा का जवाब हिंसा से ही मिलेगा।'

अमेरिका और ईरान के बीच जंग की चिंगारी फिर भड़कने लगी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे कारगो शिप पर ईरानी हमले से ट्रंप प्रशासन बौखला गया है। ताजा कार्रवाई में अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया। इधर, अमेरिका द्वारा किए गए रातभर के हवाई हमलों के बाद ईरान ने भी शनिवार को बहरीन में ड्रोन अटैक और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज पर भी हमला किया।

अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला

अमेरिकी हमले के बाद इस्लामिक रिवाय्शुनरी गार्ड कौन्सिल (आईआरजीसी) ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी ठिकानों पर ये हमले तब हुए जब आईआरजीसीने वाशिंगटन को धमकी दी कि पहले हुए हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा और तेहरान इसका निर्णायक जवाब देगा।



स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दुनिया फिर चिंतित
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे बिजली समृद्ध व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहां पर इन दोनों देशों में एक बार फिर सीजफायर खत्म होते देख दुनिया की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस क्षेत्र से सप्लाई सामान्य होने पर जीवाश्म ईंधन की कीमतें भी सामान्य रहती हैं लेकिन यह मार्ग डिस्टर्ब होने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतें प्रभावित होती हैं। दुनिया की कुल मांग का 20 फीसदी कच्चा तेल इसी रास्ते से पास होता है।

ट्रंप ने होर्मुज में कारगो शिप पर हमले के जवाब में किया पलटवार
अमेरिका द्वारा किए गए रातभर के हवाई हमलों के बाद ईरान ने शनिवार को बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जबकि दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज पर भी हमला हुआ। बहरीन पर ईरान का हमला संयोग नहीं माना जा रहा है। बहरीन ईरान के सबसे मुखर आलोचकों में से एक है और वहां अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय भी स्थित है। हाल ही में बहरीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी की थी, जहां खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी।

हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर सड़क, भारत आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति!



एजेसी ►► नई दिल्ली

भारत-अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव के बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। अपने नाम पर सड़क बनाए जाने को ट्रंप ने अनोखा पल बताया है और इसके लिए लिए भारत का आभार जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर सोशल पर उद्घाटन समारोह की तस्वीर शेयर करते हुए इसे अभूतपूर्व सम्मान बताया। बता दें, कुछ दिन पहले तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम बदलकर 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखा है। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत-अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने में हैदराबाद की भूमिका को आगे लाना है।

यहां पर है यह सड़क
यह सड़क नानकरामगुड़ा के फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहां कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय टेक कंपनियों के दफ्तर भी काम कर रहे हैं। इस सड़क के नाम की पट्टी (नेमप्लेट) का उद्घाटन इसी हफ्ते एक कार्यक्रम में किया गया था। इस मौके पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर सहित तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल, यह पूरा आयोजन अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न से जुड़ा था।

15 साल पुरानी कार में सैफ्टी सिस्टम अचानक हुआ एक्टिव

महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में स्टालिन की डीएमके को एक और झटका लगा है। एमडीएमके ने औपचारिक रूप से डीएमके के साथ अपना नौ साल पुराना गठबंधन समाप्त कर दिया है। हालांकि उसने सत्तारूढ़ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह नियमित पार्टी की आम सभा की बैठक में लिया गया। अपने प्रस्तावों में एमडीएमके ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार का स्वागत किया और उससे प्रमुख चुनावी वादों पर अडिग रहने का आग्रह किया। जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाए रखना और मेकेंदातु बांध परियोजना जैसे मुद्दों पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। प्रस्तावों में टीवीके गठबंधन में शामिल होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

खड़ी कार का एयरबैग खुलने से युवक की मौत

नीट का 1 सवाल झूँप, 20 लाख छात्रों को मिलेंगे 4 बोनस अंक



एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज
ठाणे पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि कार भले ही पुरानी थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उसके पास वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट था। पुलिस ने मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है। पुलिस जांच के लिए ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स से भी सलाह ले रही है। एयरबैग खुलने की स्प्रीड 200 से 300 किमी/घंटा के बीच हो सकती है। इस वजह से तेज झटका लगता है। इससे बचने के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। सीट बेल्ट ना लगाने की स्थिति में जोरदार झटका लगने से गंभीर चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है।

नई दिल्ली। नीट यूजी2026री-एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले ही उम्मीदवारों के 4 नंबर पक्के हो गए हैं। 21 जून को हुए री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई है, जिसमें फिजिक्स के एक सवाल को 'ड्रॉप' (हटाया) गया है। ड्रॉप किए गए इस सवाल के लिए सभी छात्रों को पूरे 4 बोनस नंबर (+4) दिए जाएंगे, बल्कि किसी उम्मीदवार ने उस सवाल को हल किया हो या नहीं किया हो। 20 लाख उम्मीदवारों ने री-एग्जाम दिया है और इन सभी को अपने फाइनल रिजल्ट से पहले एक सवाल के नंबर पता चल गए हैं। इसके अलावा फिजिक्स के ही एक सवाल के दो जवाब सही पाए गए हैं। जिन- जिन कैडिडेट्स ने उन दोनों विकल्पों में से किसी को भी चुना होगा।

एक सवाल झूँप होने के बाद 20 लाख कैडिडेट्स 4 बोनस अंक
नीट एग्जाम 2026 फाइनल आंसर-की आने के बाद यह साफ होगा कि क्या कोई और सवाल झूँप किया गया है। नीट पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है तो सभी 20 लाख को 4 बोनस अंक मिलेंगे। फिजिक्स के साथ- साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी एक या दो सवाल के गलत होने की आशंका जताई जा रही है।



गैस बकरा मत बनो

एसिडिटी अपच पेट फूलना

30 DAY CHALLENGE

जड़ से पाचन Strong

झटपट राहत यानी समस्या बार-बार वापस



शुरु करो!

इंड पंचारिष्ट

30 DAY CHALLENGE

जड़ से पाचन Strong

झटपट राहत यानी समस्या बार-बार वापस



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARGAPUR

विज्ञापन संख्या : R/05/2026 दिनांक 10 जून 2026

संस्थान निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता है।

(1) पेशेवर प्रशिक्षु (वित्त एवं लेखा) - 10 पद

शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अद्यतन जानकारी के लिए <http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions> पर जाएं।

cbc21255/11/0003/2627 कुलसचिव / Registrar

मन-जीवन को कर रहा अशांत सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस



कवर स्टोरी / डॉ. मोनिका शर्मा

कभी किसी परिचित के सुंदर घर की तस्वीर तो कभी किसी फ्रेंड के विदेश घूम आने के अपडेट, वर्चुअल दुनिया में जुड़े किसी अनजान वर्चुअल मित्र ने अचानक अपना लुक बदल लिया, तो किसी के बच्चों की कमाल की उपलब्धियां। सब कुछ स्क्रीन के जरिए हम तक पहुंचता रहता है। हर उम्र के लोगों में लगातार

जबकि वास्तविकता यह है कि किसी के भी जीवन की हकीकत इतनी सुंदर-सहज नहीं होती है, जितनी सोशल मीडिया पर दिखती है। ऐसे में बनावटी-सजावटी आभासी दुनिया के बहकावे में आने के बजाय अपने मन-जीवन को साधना जरूरी है।

बढ़ने लगी है तुलनात्मक प्रवृत्ति

आज के दौर में स्क्रीन के जरिए दस्तक देता कंटेंट, हर उम्र के लोगों को कमतरी और बेहतरी के जाल में उलझा रहा है। शुभ कार्य हों या कोई व्यक्तिगत उपलब्धि, आभासी दुनिया में अजीब

से नाप-तौल वाले मनोभावों से देखी, समझी और स्वीकारी जाने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर फैमिली ग्रुप्स में शेयर की जाने वाली सूचनाओं और क्लिक्स तक, हर बात और जज्बात तुलना करने की सोच की ओर धकेल रहा है। इसके चलते मन में आने वाली अनचाही तल्खी, व्यावहारिक जिंदगी की भरपूर समझ होने के बावजूद, दिलो-दिमाग को बोझिल कर रही है। सुंदरता, सहृदयता और संपन्नता की जो चमक स्क्रीन पर तैरते अपडेट्स में दिखती है, वही जीवन का सच नहीं है, यह जानते-बूझते हुए भी रंग-रूप, कद-काठी और उपलब्धियों से लेकर खुशियों और उत्सवीय रंग-रंग तक एक असंतोष की भावना पनप रही है। ध्यान रहे कि सोशल मीडिया के जरिए क्लिक भर में आप तक पहुंच जाने वाले कंटेंट से तुलना का भाव स्वयं यूजर्स में तो बढ़ ही रहा है। बाजार ने भी इसे बढ़ाया

है क्योंकि यह भी एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है।

गहरा होता है कमतरी का भाव

जाने-अनजाने लोगों के अपडेट्स देखकर पैदा हो रहा तुलना का भाव, खुद के जीवन में कमियां देखने को प्रेरित कर रहा है। इसके चलते हमारा मन रिशतों, जीवनशैली और अपने हिस्से आए स्टाइल-सम्मान की भी अनदेखी करने लगता है। नतीजतन जिंदगी की नेमतों को लेकर शुक्रिया कहने के भाव की जगह शिकायतों ने ले ली है। नोटिफिकेशन टोन के साथ पल-पल में अवतरित

स्पेशल: वर्ल्ड सोशल मीडिया-डे, 30 जून

आज के दौर में अधिकांश लोग किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाल के सालों में देखने में आ रहा है कि इन पर दिन में कई-कई बार आने वाले नोटिफिकेशंस से लोगों का मन-जीवन बेचैन और अशांत होता जा रहा है। इसके पीछे वया वजहें हैं, इनका वया प्रभाव पड़ता है और इनसे कैसे बच सकते हैं, आपको जरूर जानना चाहिए।



होते संदेश, सूचनाएं, चित्र, असंतुष्टि भरी सोच और बेचैनी भी साथ लाते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि वर्चुअल दुनिया में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे जाने-अनजाने चेहरों के अपडेट्स हर उम्र के लोगों के लिए व्यक्तिगत जीवन में असंतुष्टि की बड़ी वजह बन रहे हैं। स्मार्ट गैजेट्स की स्क्रीन के जरिए अमूमन अपनों-परायों तक अपनी कमियां, कमजोरियां और दिल की कसक नहीं पहुंचाई जाती। यह जानते-समझते हुए भी दूसरों के चमकदार, सफल और सुखी दिखते जीवन की वर्चुअल आभा में खुद को कहीं कमतर महसूस करने का भाव पनपने लगता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक आमतौर पर सोशल मीडिया पर लोग अपने बारे में सकारात्मक जानकारी ही प्रस्तुत करते हैं। फिल्टर्स का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को और प्रभावी बना देते हैं। इसके चलते यह लगने लगता है कि हमारे मित्र या संबंधी कितने सुंदर हैं। कितने सफल हैं! ऐसे में हम उस सुख को भी भूल जाते हैं, जो हमारी झोली में मौजूद होते हैं। इसकी वजह यह भी है कि वास्तविक दुनिया में तुलना करने के दायरे में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। सोशल मीडिया का डिजिटल यूनिवर्स, दूसरों के साथ तुलना करने की स्थितियों को कई गुना बढ़ा देता है। समझना जरूरी है कि दूसरों की जिंदगी के वर्चुअल अपडेट्स में दिखने और होने के फर्क को समझते हुए अपने जीवन की सहजता को बनाए रखिए। अपनी खुशियों को जीने से दूरी मत बनाइए *

खो रहें सहज-सी खुशियां

लगातार मिलने वाले सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस के जरिए ईसानी व्यवहार और विचार में चाहे-अनचाहे स्क्रीन पर दिखी तस्वीरों, सूचनाओं और उपलब्धियों का ही लेखा-जोखा रहने लगता है। ऐसे में हम उस सुख को भी भूल जाते हैं, जो हमारी झोली में मौजूद होते हैं। इसकी वजह यह भी है कि वास्तविक दुनिया में तुलना करने के दायरे में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। सोशल मीडिया का डिजिटल यूनिवर्स, दूसरों के साथ तुलना करने की स्थितियों को कई गुना बढ़ा देता है। समझना जरूरी है कि दूसरों की जिंदगी के वर्चुअल अपडेट्स में दिखने और होने के फर्क को समझते हुए अपने जीवन की सहजता को बनाए रखिए। अपनी खुशियों को जीने से दूरी मत बनाइए *



अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहीं देश की निजी स्पेसटेक कंपनियां

अचीवमेंट संजय श्रीवास्तव

हाल में 'गैलेक्सआई' द्वारा मिशन दृष्टि नामक दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद दुनिया भर की मीडिया में भारत की निजी स्पेस कंपनियों की कम लागत के साथ तकनीकी दक्षता तथा इस आधार पर वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में उनकी तीव्र बढ़त की चर्चा हो रही है।

गैलेक्सआई ने रचा इतिहास: जब भारत ने 'मिशन दृष्टि' के तहत 190 किलो वजन की दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया, तब बहुतें ने गैलेक्सआई का नाम पहली बार सुना। देश ने स्पेस तकनीकी क्षमता का लोहा वैश्विक स्तर पर मनवाया हो और खबरों में इसरो की जगह देश के सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बनाने वाली किसी ऐसी निजी कंपनी का नाम सुर्खियों में शामिल हो, जिसके अस्तित्व में आए महज पांच साल हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतने कम समय में यह अनूठी सफलता हासिल कर इसने बता दिया है कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति कितनी तेज गति से हो रही है।

बहुपयोगी है इसकी तकनीक: गैलेक्सआई द्वारा लॉन्च मिशन दृष्टि की ऑप्टोसार तकनीक में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल यानी ईओ और सिंथेटिक, पंचर रडार या एसएआर सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। इस संयोजन के कारण यह उपग्रह हर मौसम और दिन-रात में डेटा संग्रह करने में सक्षम है। यह क्षमता अब तक सीमित देशों या अलग-अलग प्रणालियों में बंटी हुई थी, जबकि भारत ने इसे एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपीय देश पृथ्वी अवलोकन में अग्रणी रहे हैं, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से 'गेम चेंजर' ऑप्टोसार तकनीक जैसी एकीकृत प्रणाली भारत को तकनीकी बढ़त देती है। यह उपग्रह सेना को डेढ़ मीटर के दायरे में सीमा पार की सटीक जानकारी देगा। कृषि मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता व्यापक है। बाढ़ या चक्रवात के समय यह त्वरित और सटीक डेटा निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता

भारत के सरकारी स्पेस इंस्टीट्यूट इसरो की उपलब्धियां तो जगजाहिर हैं ही, अब इसी के नगणेकदम पर चलते हुए कई स्पेसटेक निजी कंपनियां भी देश-दुनिया में अपनी धाक जमा रही हैं। स्पेसटेक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाई हासिल कर रही देश की प्राइवेट स्पेसटेक कंपनियों की अचीवमेंट पर एक नजर।

हाल में 'गैलेक्सआई' द्वारा मिशन दृष्टि नामक दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद दुनिया भर की मीडिया में भारत की निजी स्पेस कंपनियों की कम लागत के साथ तकनीकी दक्षता तथा इस आधार पर वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में उनकी तीव्र बढ़त की चर्चा हो रही है।

गैलेक्सआई ने रचा इतिहास: जब भारत ने 'मिशन दृष्टि' के तहत 190 किलो वजन की दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया, तब बहुतें ने गैलेक्सआई का नाम पहली बार सुना। देश ने स्पेस तकनीकी क्षमता का लोहा वैश्विक स्तर पर मनवाया हो और खबरों में इसरो की जगह देश के सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बनाने वाली किसी ऐसी निजी कंपनी का नाम सुर्खियों में शामिल हो, जिसके अस्तित्व में आए महज पांच साल हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतने कम समय में यह अनूठी सफलता हासिल कर इसने बता दिया है कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति कितनी तेज गति से हो रही है।

बहुपयोगी है इसकी तकनीक: गैलेक्सआई द्वारा लॉन्च मिशन दृष्टि की ऑप्टोसार तकनीक में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल यानी ईओ और सिंथेटिक, पंचर रडार या एसएआर सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। इस संयोजन के कारण यह उपग्रह हर मौसम और दिन-रात में डेटा संग्रह करने में सक्षम है। यह क्षमता अब तक सीमित देशों या अलग-अलग प्रणालियों में बंटी हुई थी, जबकि भारत ने इसे एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपीय देश पृथ्वी अवलोकन में अग्रणी रहे हैं, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से 'गेम चेंजर' ऑप्टोसार तकनीक जैसी एकीकृत प्रणाली भारत को तकनीकी बढ़त देती है। यह उपग्रह सेना को डेढ़ मीटर के दायरे में सीमा पार की सटीक जानकारी देगा। कृषि मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता व्यापक है। बाढ़ या चक्रवात के समय यह त्वरित और सटीक डेटा निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता

भारत के सरकारी स्पेस इंस्टीट्यूट इसरो की उपलब्धियां तो जगजाहिर हैं ही, अब इसी के नगणेकदम पर चलते हुए कई स्पेसटेक निजी कंपनियां भी देश-दुनिया में अपनी धाक जमा रही हैं। स्पेसटेक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाई हासिल कर रही देश की प्राइवेट स्पेसटेक कंपनियों की अचीवमेंट पर एक नजर।



सही नहीं सबका पीछा करना

दूसरों के मीडिया अपडेट्स के चलते अज में आ रही खिन्नता लोगों को उनका फॉलोअर बना देती है। हम हरदम यह जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि उनके ताजा अपडेट्स क्या हैं? आज उनकी क्या गतिविधियां हैं? अक्सर लोग उनकी कैप्शे और कितनी सराहना कर रहे हैं? दूर बैठे लोगों की जिंदगी का पीछा करने की सोच से ऐसी बातों के चलते खुद आपके जज्बात बदलने लगते हैं। मन-जीवन में असंतोष भरी स्याह उदासी जगह बना लेती है। यहां तक कि ईश्या का भाव भी पनपने लगता है। सोचने वाली बात यह है कि यह सब होने की कोई वास्तविक वजह ही नहीं होती है। सोच-समझकर दी गई जानकारीयां और बना-संवारकर साझा की गई तस्वीरें लोगों को हैराण-परेखाण करती हैं, जबकि खुद उनके ही द्वारा साझा की जा रही सामग्री के इतर उनके जीवन की असलियत का दूसरों को कोई अंदाजा ही नहीं। ऐसे में यह आदत बेवजह आपकी ऊर्जा और समय खपावे लगती है। सोशल मीडिया का उपयोग यूजर्स जिस इरादे से करते हैं, उनके मन-मस्तिष्क पर देखा ही असर पड़ता है। बिना सोचे-समझे दूसरों के अपडेट्स के इंतजार में स्क्रीन स्कॉल करने से अवसाद और घबराहट पैदा होती है। जिन लोगों के अपडेट्स मन में मटकवाय या नकारात्मक भाव लाते हैं, उन्हें अनफॉलो कीजिए। हितित और उदास महसूस करवाने वाले कंटेंट से दूरी बनाएं। वर्चुअल दुनिया हो या असल संसार औरों से ज्यादा अपनी जिंदगी में रूचि रखिए।



गजल भूल गए हैं लोग सलीका

भूल गए हैं लोग सलीका आम्रगण का, भाव नहीं दिखता आंखों में अप्रणेय का। भ्रमगने दाते पेड़ों की भीड़ लगी है, मोल नहीं होता कानन में श्रव चंदन का। याद किसी की आने पर सर दीवारों से टकराए तो दोष नहीं होता दरपन का। इकीदिन उग्र ठला करती है सबकी जग में, धीरे-धीरे रंग अतरता है आनन का। साथ न हो गर मन का मीत सफर में नदरगं लगने लगता है हर मौसम फिर बेगन का।

आजकल समाज में शादी-ब्याह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों के बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा और धैर्य की परीक्षा का महायज्ञ बन गया है। यह वह अवसर होता है, जब एक अदना-सा ईसान अचानक शादी समारोह प्रबंधक बन जाता है और अपनी सारी जमापूंजी, साख और यहां तक कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए रखी गई पूंजी भी एक रात के दिखावे में झोंक देता है।

समारोह में दुल्हन को इतना पेंट किया जाता है कि पेंट किया हुआ घर भी फीका दिखने लगता है। चेहरे पर पुताई की इतनी परतें होती हैं कि अगर दुल्हन को छींक आ जाए, तो आस-पास के लोग उस गुबार से लाल हो जाएं। इसे ब्राइडल ग्लो कहा जाता है, जो सुबह होते ही वॉटरप्रूफ न होने की स्थिति में बह जाता है। आम धारणा है कि दुल्हन का लहंगा भी उतना ही भारी होना चाहिए, जितना दुल्हन के पिता का सिर कर्ज के बोझ से भारी हो जाता है।

शादी समारोह अब रिशतों का उत्सव कम और कॉम्पिटिशन ज्यादा बन गया है। पड़ोसी की बेटी की शादी में पचास पकवान थे, तो हमें शुभ इक्यावन करने ही होंगे। चाहे इसके लिए पिता को क्या न बैंक से लोन लेना पड़े। लगन के इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभाव उस मध्यमवर्गीय पिता पर होता है, जो तीन घंटे के दिखावे के लिए तीस साल की कमाई स्वाहा कर देता है। मेहमानों को खिलाने के लिए मेनू में तरह-तरह के व्यंजन होते हैं, जिसमें से अधिकतर मेहमान केवल वही स्पेशल डिश खाते हैं, जो उनके घर में नहीं बनते हैं। मेहमान इन पकवानों पर ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे इसके बाद कभी

लंग्य / सूर्यदीप कुशवाहा

मेहमान इन पकवानों पर ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे इसके बाद कभी उन्हें खाना मिलेगा ही नहीं। एक तरफ मेहमान पकवान उड़ाते हैं, उधर लड़की के बाप का बीपी बढ़ता जाता है।

शादी का झमेला



पिता को कोस और लताड़ सकते हैं। लेकिन समारोह का असली मजा या सजा सड़क पर बासत के रूप में मिलता है। डीजे वाले बाबू चाहे कैसा भी गाना बजाएं, बारतियों को तो बस वही एक स्टेप आता है-नागिन डांस। ऐसा लगता है जैसे सांपों ने पूरी बारात को डस लिया हो। दूल्हा घोड़ी पर बैठा ऐसे मुस्कराता है, जैसे उसने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता हो, जबकि सच्चाई यह है कि वह कुछ ही देर में स्वतंत्रता से परतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने वाला होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार हो। शायद इसीलिए आज के दौर में शादी समारोह समाज के सामने अपनी औकात बताने का एक जरिया बन गया है। शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन शान से सड़ कार में घूमते हैं और पीछे दुल्हन के पिता उस कार की ईएमआई भरते हैं। इसे ही लड़की का बाप कहते हैं। *



त्रासदी, बेरोजगार युवाओं की बेचैनी, इंटरनेट ठगी और आभासी रिशतों के खोखलेपन जैसे समकालीन विषयों को अत्यंत संवेदनशीलता से उठाया है। वे केवल दुख की दास्तां नहीं सुनाते, बल्कि जीवन की कठोर परिस्थितियों के बीच मनुष्य की जिजीविषा और छोटे-छोटे सुखों की तलाश को भी रेखांकित करते हैं। उनकी भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण और आज के जीवन के जीवंत मुहावरों से भरपूर है। संवादों में स्वाभाविकता है, जिससे पात्र पाठक के बेहद करीब आ जाते हैं। हालांकि, विविध विषयों के कारण कहीं-कहीं कथ्य का हल्का बिखराव दिखाई देता है, फिर भी उनकी रचनात्मक ईमानदारी और मानवीय दृष्टि इस कमी को ढंक लेती है। *

पुस्तक: आवारा अदकार (कहानी संग्रह), लेखक: विक्रम सिंह, मूल्य: 250 रुपए, प्रकाशक: लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज

संवेदना-संघर्ष का कथालोक

हाल में प्रकाशित हुआ विक्रम सिंह का कहानी-संग्रह 'आवारा अदकार' समकालीन जीवन की जटिलताओं, विडंबनाओं और मानवीय संघर्षों के दस्तावेज की तरह है। उनकी कहानियों में गंम और यशार्थ की खुरदुरी जमीन दिखाई देती है, तो दूसरी ओर कल्पना की ऐसी ऊंचाई भी, जो साधारण जीवन को अर्थपूर्ण बना देती है। यही कारण है कि उनकी कहानियां केवल घटनाओं का विवरण नहीं लगती, बल्कि पाठक के भीतर संवेदना और विचार दोनों को जागती हैं। लेखक ने खाड़ी देशों में संघर्षरत मजदूरों की पीड़ा, कोरोना काल की

MUSHROOMEX[®] मशरूम पाउडर

वजन बढ़ाय के सही तरीका ला अपनावव, आयुर्वेदिक की 12+ जड़ी बूटियों से निर्मित मशरुमेक्स मशरूम पाउडर

🍄 - 100% आयुर्वेदिक

🌱 - 10 दिनों में असर दिखना शुरू

📉 - नो साइड इफेक्ट्स

2 करोड़+ संतुष्ट ग्राहक

MRP ₹332 /-

आपके नज़दीकी सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध !

Also Available at : www.mymushroomworld.com | [amazon](#) | [Flipkart](#)

Mushroom World Ayurved & Food Pvt. Ltd.

For Trade Enquiry - +91 888 922 3333

[🍽️] तरकश

निर्लंबन और पनिशमेंट का महीना!

विधानसभा के मानसून सत्र और मंत्रिमंडल की सर्जरी की दृष्टि से जुलाई महीना छत्तीसगढ़ के लिए खासा महत्वपूर्ण रहेगा, तो कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए काफी संवेदनशील भी। संवेदनशील मतलब खतरा भरा। दरअसल, जुलाई में सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया जाना है। हेल्पलाइन का अच्छा रिसांस मिल रहा है। लोग लगातार अपनी बातें फोन कॉल के जरिये रख रहे हैं। शिकायतों के संबंध में आवेदकों को प्रॉपर रिहाई कर उनसे पेपर भी मंगाए जा रहे हैं। याने कंप्लेन को सिर्फ छोड़ दिया जा रहा, बल्कि संपर्क कर साक्ष्य जुटाए जा रहे। सीएम सचिवालय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा। एकसरसाइज इसलिए किया जा रहा कि सीएम हेल्पलाइन की वाजिब शिकायतों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करने की मन:स्थिति बना ली है। खासकर, करप्शन और लापरवाही के मामलों में। जाहिर है, जुलाई महीना कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए निर्लंबन और पनिशमेंट वाला रहेगा। सरकार का कहनाई है कि लोगों में सीएम हेल्पलाइन का भय हो। सही भी है...एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने काफी पहले हेल्पलाइन बना लिया था और उन्हें इसका फायदा मिला।

मंत्रियों का दिल्ली प्रवास

विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल का फेरबदल मुमकिन प्रतीत नहीं हो रहा। वैसे भी पहले मोदी कैबिनेट में बदलाव होना है। उसके बाद ही राज्यों का नंबर आएगा। हालांकि, सर्जरी के लिए एक्सरसाइज प्रारंभ हो चुका है। मंत्री, विधायकों का दिल्ली जाना जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और हेल्थ मिनिस्टर श्यामबिहारी जायसवाल इस हफ्ते दिल्ली गए तो उसके अगले दिन पूर्व मंत्री लता उसेंडी दिल्ली में थी। 29 जून को स्कूल शिक्षा मंत्री गर्जेंद्र यादव दिल्ली जा रहे हैं। बताते हैं, सच कार्यालय से उन्हें बुलावा है। जाहिर है, लता उसेंडी का नाम मंत्री बनने वालों की चर्चाओं में सबसे उपर है, तो यूपी चुनाव को देखते गर्जेंद्र यादव का भी कद बढ़ाया जा सकता है। गर्जेंद्र को एकाध और विभाग मिल सकता है। वैसे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि किसी डिप्टी सीएम का विस्फट अगर गिरा तो फिर गर्जेंद्र का प्रमोशन भी हो जाए...आखिर राजनीति मुकद्दर का खेल तो है।

माननीयों के स्टाफ और नया टीहा

वैसे विष्णुदेव कैबिनेट में पांच मंत्रियों के बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। मगर बीजेपी का कोई भरोसा नहीं, संख्या इससे उपर भी जा सकती है। बहरहाल, जिन पांच मंत्रियों की विदाई की अटकलें तेज हैं, उनके घरों और आसपास के लोगों में माहौल भारी हो गया है। असल में, पांच मंत्रियों के खिलाफ परसेप्शन इतना गहरा है कि सोशल मीडिया में लोग खुलूआम ऐलान कर रहे हैं, फलां-फलां मंत्री...। और लोग उस पर ऐतबार भी कर ले रहे, क्योंकि रिपोर्ट काई ही उनका ऐसा है...ढाई साल उन्होंने सिर्फ अपने लिए काम किया। खैर, इन मंत्रियों के पीए, स्टॉफ, कारोबारी और समर्थक अपने अगले ठीहें की संभावनाएं तलाशने में लग गए हैं।

जुगाड़ का डिप्टी कमिश्नर

जुगाड़ की माया देखिए...कुछ बरस पहले छत्तीसगढ़ टूरिस्म बोर्ड में राजस्थान का एक व्यक्ति पर्यटन अधिकारी बना। इसमें अधिकारी जरूर जुड़ा है, मगर वास्तव में यह कलास श्री का पद होना है। खैर, कुछ दिनों बाद उन्होंने जोर-जुगाड़ लगाकर रायपुर से दिल्ली के सूचना केंद्र में पोस्टिंग करा ली। और, उसके बाद अब प्रतिनिधुक्ति पर रेंजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर बन बैठे। दरअसल, रेंजिडेंट कमिश्नर श्रुति सिंह ने इस बात को आधार बनाकर नोटशीट भेजा कि फलां पर्यटन अधिकारी का वेतन डिप्टी कमिश्नर के समतुल्य हो गया है और जीपीडी से उस पर मुहर लग गई। जबकि, रायपुर में उनके सारे बैचमेट 18 साल बाद भी पर्यटन अधिकारी से उपर नहीं पाए हैं। जाहिर है, बाबू के सीनियर हो जाने पर उसकी भी तनख्वाह असिस्टेंट कलेक्टर के बराबर हो जाती है तो क्या उसे असिस्टेंट कलेक्टर बना दिया जाएगा। बहरहाल, इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली का रेंजिडेंट कमिश्नर ऑफिस बाकी राज्यों की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, न कि बाबू केडर के लोगों को वहां बिठा दिया जाए।

कमरा नंबर 109 का रहस्य

2016 में दिल्ली में जब छत्तीसगढ़ सदन बना, तब नियम बना था कि उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा और किसी को कमरा नहीं मिलेगा। विधायकों, सांसदों को भी नहीं। मगर छत्तीसगढ़ के एक मंत्री के कथित पीए ने करीब साल भर से कतन में कमरा नंबर 109 हथिया रखे हैं। अब आप पूछेंगे, कथित पीए क्यों? कथित इसलिए कि किसी मंत्री को दिल्ली में काम करने के लिए पीए नहीं मिलता। वास्तव में पीए होते तो वे मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में रहते। किसी और मंत्री का पीए तो दिल्ली में नहीं रहता। यहां तक कि किसी मुख्यमंत्री के पीए की भी पोस्टिंग दिल्ली में नहीं होती। फिर कमरा नंबर 109 का रहस्य क्या है? स्टेट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को इसे नोटिस में लेना चाहिए...पता यह भी लगाना चाहिए कि रेंजिडेंट कमिश्नर ऑफिस के किस मुलाजिम का मोदी विरोधी नेता से सीधा कनेक्शन है।

पोस्टिंग के लिए 10 पेटी

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले में चल रही तीन-पांच की चर्चाओं को देखते सरकार ने ट्रांसफर लिस्ट रोक दी थी। मगर इसके भीतर की जो बातें निकल कर कर आ रहीं, वो हैरान करने वाली हैं। किसी ने बताया कि एक राग्रसे अधिकारी ने सिर्फ जिले में जाने के लिए एक बड़े बिचौलिये को 10 पेटी दे डाला। हालांकि, इस पर सहसा यकीं नहीं होगा...आखिर वो 10 पेटी निकालेगा कैसे? जवाब मिला, वो डेड-दो महीने में निकाल लेगा। वो वैसा ही करेगा, जैसा आजकल जिलों में हो रहा। बहरहाल, कई लोगों का पैसा इबता लर रहा है। जिन बिचौलियों ने पैसा लिया है, वे पिछले तीन महीने से दिलासा दे रहे हैं, बस लिस्ट निकलने ही वाली है। मगर सरकार टस-से-मस नहीं हो रही।

पोस्टिंग और किस्मत

बस्तर आईजी के लिए 2004 बैच के दो आईपीएस अफसरों के नामों की बड़ी चर्चा थी। मगर आखिरकार पोस्टिंग मिल बढ़ी नारायण मीणा को। बढ़ी वैसे शुरू से पोस्टिंग को लेकर काफी किस्मती रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक नौ जिलों के पुलिस अधीक्षक रहने का रिकार्ड उन्हीं के नाम है, तो एक साथ दो पुलिस रेंज के आईजी रहने वाले वे सबे के बाद आईपीएस अधिकारी हैं। बड़ी छत्तीसगढ़ के चुनिंदा आईएस, आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें सरकार बर्कलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रमन सरकार में वे सात जिलों के एसपी रहे तो भूपेश सरकार में दो जिलों के एसपी और तीन रेंज के आईजी बनने का उन्हें मौका मिला। वे दुर्ग में एसपी रहे और वहीं प्रमोट होकर आईजी बन गए। फिर बिलासपुर के आईजी बने और वहां से फिर दुर्ग आए और दुर्ग के साथ-साथ रायपुर के भी आईजी। ऐसा पोर्टफोलियो पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा का भी नहीं रहा। जुनेजा पुलिस महकमे के सबसे किस्मती पुलिस अधिकारी माने जाते थे। सरकार किसी की भी रही, वे कभी लूप लाइन की पोस्टिंग नहीं की। रमन सरकार के दौरान इंटेलिजेंस चीफ होने के बाद भी वे भूपेश बघेल सरकार में डीजीपी बने और विष्णुदेव साय सरकार में तमाम विरोधों के बाद भी न केवल उन्होंने कंटिन्यू किया, बल्कि छह महीने का एक्सटेंशन भी मिल गया।

आईएफएस की छुट्टी

आईएसएस ऋचा शर्मा के एसीएस फॉरेस्ट रहने के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने आईएफएस अधिकारियों को छुट्टी समेत कुछ फाइलें अपने अधिकार में ले लिए थे। दरअसल, ऋचा के फॉरेस्ट में रहने के समय आईएफएस अधिकारियों को छुट्टी लेना आसान नहीं था। सख्त आईएसएस अफसर माने जाने वाली ऋचा शर्मा काफी किंतु-परंतु, क्वेरी के बाद अवकाश स्वीकृत करती थी। लिहाजा, वन मंत्री ने अफसरों को छुट्टी का अधिकार अपने पास रख लिया था। अब ऋचा शर्मा फॉरेस्ट से हट गई हैं तो वन मंत्री ने नए एसीएस फॉरेस्ट मनोज पिंपुआ को आईएफएस अधिकारियों के छुट्टियों के अधिकार दे दिए हैं।

सीएस की SOM मीटिंग

विकास शील के चीफ सिक्रेट्री बनने के बाद दो-से-तीन हफ्ते के बीच एक

सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग (SOM) होती है, जिसे अफसरों के बीच SOM मीटिंग कहा जाता है। इसमें सभी विभागों के सिक्रेटी शामिल होते हैं। इस मीटिंग को लेकर सचिवों में काफी तनाव रहता है...सीएस न जाने क्या पूछ दें, कब टोक दें। छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस तरह की मीटिंग पहली बार हो रही। इसमें लोक सेवा गारंटी से लेकर ई-ऑफिस जैसे तमाम प्वाइंट होते हैं, सीएस जिसका फॉलोअप लेते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये जस्ट रिमाइंडर जैसी बैठक होती है, जिसमें सीएस जो टास्क दिए रहते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। सोम मीटिंग के फेर में सिक्रेट्री लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता। इससे मंत्रालय की वर्किंग स्मूथ हुई है। फिर चीफ सिक्रेट्री का भय तो है ही, वे बोलने और टोकने में गुरेज नहीं करते।

चतुर मंत्री और आईडिया

सुनिल कुमार जब चीफ सिक्रेट्री थे, तब समन्वय से ट्रांसफर या अफसरों का डेपुटेशन कराना काफी कठिन था। मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह या उनके सचिवालय से कोई मैसेज आ जाए तो बात अलग है वरना, वे नोटशीट पर इतना तगड़ा नोट लिख देते थे कि फिर फाइल को डंप करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। उस समय होशियार मंत्री या अफसर कई बार सीधे मुख्यमंत्री से नोटशीट पर लिखवा लेते थे। अब मुख्यमंत्री ने अगर ओके कर दिया तो फिर चीफ सिक्रेट्री को उस अनुमोदन देना ही पड़ेगा। फिर सुनिल कुमार भी कुछ नहीं कर पाते थे। वर्तमान चीफ सिक्रेट्री विकास शील के दौर में भी अब चीर्ज उतनी आसान नहीं। विभिन्न विभागों से आए उंच-नीच वाले प्रस्तावों पर वे ब्रेक लगाने का प्रयास करते हैं। बताते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के जंबो ट्रांसफर के प्रपोजल पर भी उन्होंने ब्रेक लगाया।

मंत्री का अधिकार सर्वोच्च

वन मंत्री केदार कश्यप ने आईएफएस अधिकारियों के अवकाश का अधिकार अपने पास रख लिया था, इस प्रसंग से सवाल उठता है, क्या कोई मंत्री ऐसा कर सकता है। बता दें, सविधान में मुख्यमंत्री को सरकार माना गया है...मंत्रियों के सारे अधिकार मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। मुख्यमंत्री सरकार के कामकाज में सुविधा के लिए मंत्री बताते हैं मगर वे चाहे तो किसी भी मंत्री के आदेश को पलट सकते हैं। उसी तरह सचिवों के सारे अधिकार मंत्री में समाहित होते हैं। मंत्री चाहे तो कोई भी फाइल मंगा सकता है, सचिव के नोट को बदल सकता है। ये अलग बात है कि यदि कोई गलत चीज होगी तो उसके लिए मंत्री ही जिम्मेदार होंगे। मगर सत्ता मंत्रियों की ही सर्वोच्च होती है। अब वो अलग बात है कि कई बार घुड़सवार कमजोर होता है, तो घोड़ा लगता है नचाने, वही स्थिति मंत्री और अफसर की होती है।

कलेक्टर, एसपी पर कसावट?

मुख्य सचिव विकास शील ने मंत्रालय और डायरेक्ट्रेट के अफसरों को काफी कस दिया है। मंत्रालय में 90 परसेंट अफसर अब 10 बजे पहुंच जाते हैं, तो मीटिंग, रिव्यू से सिस्टम टाईट हुआ है। मगर जिलों का हाल अभी भी डिरेल्ड है। न कलेक्टर टाईम को फॉलो कर रहे और न एसपी। अधिकांश जिलों में अराजकता जैसी स्थिति है। खासकर, उन जिलों की स्थिति काफी खराब है, जहां न प्रमोटी कलेक्टर पाए हैं। इनमें से कई ने तो जाते ही गर्द उड़ा दिया है। दरअसल, नए प्रमोटी कलेक्टरों को कहीं से भनक मिल गई कि उन्हें खानापूर्ति के लिए कलेक्टर बनाया गया है, इसके बाद कभी भी उन्हें विदा कर दिया जाएगा। इसके बाद कामधाम छोड़ वे रोज सुबह कैलकुलेटर लेकर बैठ जा रहे। खैर, कलेक्टर, एसपी अगर टाईट होने तो कोरिया में ट्रिपल थर्ड हो जाता। सोनहत का जघन्य हत्याकांड पुलिस और प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना है। रत जैसी चीजों के लिए अगर तीन-तीन हत्याएं हो जाए तो सबसे पहले कलेक्टर, एसपी को लटकाना चाहिए। मुख्य सचिव को भी जिलों की अराजकता को लेकर स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो अफसर इधर-उधर कर रहा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वे सिफारिश तो कर ही सकते हैं।

विधायकों की मजबूरी-1

छत्तीसगढ़ में रूलिंग पार्टी के विधायक हो या फिर आपोजिशन के, सभी एक सूत्रीय अभियान में जुटे हुए हैं, तो उनकी भी अपनी मजबूरी है। दरअसल, चुनाव इतने कॉन्टली होते जा रहे कि ग्रामीण सीटों पर भी अब 10 से 15 खोखा निकल जा रहा। शहरों तो 25 से उपर मानिये। ऐसे में, वो सब होंगे, जो कभी कल्पना से बाहर थे। जाहिर है, अब रत और मरुम ठेके तक पर एकाधिकार की कोशिशें हो रही। जांजीगर जिले की एक महिला विधायक का रेत माफिया से अपना हिस्सा मांगते वीडियो वायरल हुआ ही था तो कोरिया में दो बीजीपी विधायकों के रेत पर वर्चस्व में कितना बड़ा कांड हो गया, इसे सबने देखा। जघन्य वारदात हो गई। और जब विधायककी लोग ही रेत से तेल निकालने लगेंगे तो सिस्टम क्या करेगा। कलेक्टर लोग कुर्सी बचाने मौन रहना ही श्रेष्ठ समझ रहे। क्योंकि, एक तो वो दमदार वाले कलेक्टर अब बचे नहीं, दूसरा जरा सा भी टोक दिये तो फिर अगले दिन से कलेक्टर की शिकायतें शुरू। यही वो वजह है कि अच्छे खासे मार्जिन से जीतकर आए विधायकों के खिलाफ एंटी इंकांक्वेंसी तेज जा रहा।

विधायकों की मजबूरी-2

विधायकजी लोग मजबूरी में दोनों हाथ से किस तरह काम कर रहे, इसका नमूना है जिला शिक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग। सरकार ने 16 जिलों के डीईओ बदले, उनमें से छह जिलों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त किया है। दरअसल, छहों विधायकों ने जिद करके अपने जिले में नियम विरुद्ध व्याख्याताओं को डीईओ बनवा लिया। हालांकि, गर्जेंद्र यादव मजबूत बैकग्राउंड के हैं, इसलिए उन्हें नहीं झुकना था मगर मंत्रिमंडल में सर्जरी और प्रमोशन का समय है, वे भी विधायकों के प्रेशर में आ गए। बीजेपी संघटन को इसे देखना चाहिए। क्योंकि, इससे सरकार की छवि प्रभावित हो रही।

अध्यक्ष पर मंथन

इस समय सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से हैं। और यह कड़वी सच्चाई यह है कि दोनों की प्रदेश में वैसी पकड़ नहीं बन पाई है, जैसी कि पार्टी के मुखिया की होनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने तो अध्यक्ष की जगह मंत्री बनने की इच्छा जताई थी, हालांकि पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद पर कंटिन्यू कर दिया। उधर, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी ढाई साल में अपनी कोई पक़वान नहीं छोड़ पाए हैं। वास्तविकता यह है कि आज भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ही पूरे प्रदेश में एकरफरा माहौल बनाए हुए हैं। हफ्ते भर के भीतर वे दो बार सरगुजा पहुंच गए। उनके बाद विधायक देवेद्र यादव की सक्रियता है। बहरहाल, बीजेपी और कांग्रेस के सियान नेताओं को इस पर मंथन करना चाहिए बस्तर से जुड़े पार्टी नेताओं की पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता क्यों नहीं बन पाती? और क्या अध्यक्ष रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे प्रदेश के बीच के हिस्से से बनाना चाहिए?

एसपी की लिस्ट

मुख्यमंत्री के व्यस्त होने की वजह से एसपी की लिस्ट नहीं निकल पाई। मगर अब आजकल में कभी भी आदेश जारी हो सकता है। इसमें करीब 10-12 जिलों के एसपी बदले जाएंगे तो रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों चारों डीसीपी एसपी बनकर जिलों में जा सकते हैं। दरअसल, चारों 2020 बैच के आईपीएस हैं। इस बैच के एक आईपीएस नारायणपुर में काफी पहले एसपी बन चुका है। सो, इन चारों में इस बात को लेकर क्षुभ रहता है। खैर, इन चारों का नंबर इस बार लग सकता है। एसपी की लिस्ट को लेकर खुफिया चीफ अमित कुमार और सिक्रेट्री टू सीएम राहुल भगत की प्रिंसिपल सिक्रेट्री टू सीएम सुबोध सिंह के साथ मंथना हो चुकी है। इसलिए, लगता है अब ज्यादा वक्त नहीं लेगेगा। एसपी के साथ डीएसपी की लिस्ट भी निकलने वाली है।

अंत में दो सवाल आपसे?

- किस मंत्री ने सूटकेस की शक्ति के जरिये मान लिया था कि उसका कोई विकल्प नहीं है मगर अब कुर्सी डगमगा रही है?
- सरकार को सिस्टम में शुचिता लाने मंत्रियों के साथ विधायकों के उपर भी अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है?

नोटिस के बाद भी संचालकों ने न चावल जमा किया न बदले में राशि लौटाई

6 राशन दुकानों में सवा करोड़ रुपए के चावल का शार्टेज

हरिभूमि न्यूज : रायपुर।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों में चावल की हेराफेरी के मामले थम नहीं रहे हैं। वर्ष 2022 में रायपुर सहित प्रदेशभर में कई दुकान संचालकों ने हितग्राहियों को वितरण किए जाने वाले करोड़ी रुपए के चावल की हेराफेरी की थी, जिसकी शत प्रतिशत रिकवरी कई जिलों में अब तक नहीं हो पाई है। इधर रायपुर जिले में पिछले वर्ष कई दुकानों में दोबारा चावल की गड़बड़ी की गई है। इनमें से आधा दर्जन उचित मूल्य दुकानों में सवा करोड़ रुपए से अधिक के चावल की गड़बड़ी करने के मामले में संबंधित समितियों के अध्यक्ष एवं विक्रेताओं को नोटिस जारी कर चावल या बदले में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन दुकानों में से किसी ने भी चावल या राशि जमा नहीं कराई है। खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस मामले में अब एफआईआर कराए जाने की तैयारी की जा रही है।

जिला खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की कई उचित मूल्य की दुकानों में चावल शॉर्टेज की सूचना मिलने पर जांच की गई है। इस जांच के दौरान दुकान आईडी 442001039 में 315 क्विंटल, 442001020 में 385 क्विंटल, 442001040 में 1250 क्विंटल, 441001290 में 490 क्विंटल, 441001291 में 520 क्विंटल एवं 441001059 में 300 क्विंटल चावल शॉर्टेज पाया गया था। इन सभी दुकानों के संचालन करने वाली समितियों के अध्यक्ष-विक्रेताओं को नोटिस जारी कर गायब चावल के बदले चावल या राशि जमा करने के लिए कहा गया था। विभाग के इस नोटिस के बाद भी दुकानों के संचालकों ने अब तक न ही चावल जमा कराया है और न ही बदले में राशि जमा कराई है। राशन कार्ड धारकों को वितरण करने उचित मूल्य की दुकानों में पहुंचने वाले चावल को हितग्राहियों को नहीं देकर कई दुकानों के संचालक अधिक कीमत पर बाजार में खपा देते हैं। यही कारण है कि जांच के दौरान ऑनलाइन रिकार्ड में चावल की जितनी मात्रा दिखाई देती है, उसके अनुसार दुकानों में स्टॉक नहीं होता। जिन 6 दुकानों में जांच की गई, उनकी दुकानों में भी ऑनलाइन स्टॉक की तुलना में चावल कम पाया गया था।

विभागीय सूत्र से जानकारी मिली है कि उचित मूल्य की दुकानों में जितना चावल शॉर्टेज मिला था, उसमें एपीएल कोटे का चावल ज्यादा है। दुकानों में बीपीएल सहित अन्य वर्ग के कार्ड धारकों की तुलना में एपीएल कार्ड धारक चावल लेने कम पहुंचते हैं, जिसके

नियम एक महीने में नक्शा पास कराने का, खामी बताकर लटका रहे प्रकरण

हरिभूमि न्यूज : रायपुर

रायपुर निगम सीमा क्षेत्र में खाली भूखंड पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद भी लोग महीनों तक परेशान हो रहे हैं। लोक सेवा गारंटी के तहत भवन अनुज्ञा लिए जाने के साथ ही 1 रुपए की पावती लेकर इसके लिए इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निर्धारित समय सीमा में आवेदक के प्रकरण में ऑनलाइन नक्शा पास कर उपलब्ध बनाने का सिस्टम है। इसके बाद भी आवेदन के 2 से 3 माह बीतने के बाद भी प्रकरण लंबित हैं।

हालात ये है कि नगर निगम के पास हर माह औसतन 300 ऑनलाइन आवेदन नक्शा पास कराने शहर के विभिन्न हिस्सों से मिल रहे हैं, जबकि इनमें से केवल 150 आवेदक के प्रकरण में समय पर नक्शा पास कर दिया जा रहा है। 150 आवेदकों के आवेदन खामी बताकर लंबित कर दिए जा रहे हैं। दरअसल, भूखंड धारियों को नगर निगम से भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में पसीना छूट रहा है। सूत्रों के मुताबिक तीन माह नगर निवेश के पास 900 से अधिक ऑनलाइन आवेदन भवन अनुज्ञा के प्राप्त हो रहे हैं। नियम अनुसार आवेदनकर्ता को 1 रुपए की



कारण उनके कोटे का चावल का स्टॉक का वितरण भी कम हो पाता है। उचित मूल्य की दुकानों में मिलने वाला चावल एपीएल को छोड़कर अन्य वर्ग के कार्ड धारकों को नि:शुल्क मिलता है, वहीं एपीएल धारक को 10 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता है। उचित मूल्य की दुकानों में जरूर चावल का मूल्य नि:शुल्क या अधिकतम दस रुपए है, लेकिन कोचिया के माध्यम से इसी चावल को बाजार में दुकानदार 30 से 32 रुपए प्रति किलो की दर से खपाते है। इससे उन्हें जमकर मुनाफा होता है।

40 रुपए प्रति किलो की दर से लौटाना है चावल के बदले राशि चावल शॉर्टेज मिलने पर विभाग ने चावल के बदले चावल के साथ बदले में राशि लौटाए जाने का ऑप्शन रखा हुआ है। इसके तहत प्रति किलो चावल के एवज में 40 रुपए निर्धारित है। इस तरह 6 दुकानों से कुल 3260 क्विंटल चावल गायब मिला है, जिसकी 40 रुपए प्रति किलो की दर से कुल कीमत 1 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपए है।

कड़ी कार्रवाई की जाएगी

आधा दर्जन उचित मूल्य की दुकानों में कुल 3260 क्विंटल चावल शॉर्टेज मिला है। रिकवरी के लिए इन सभी दुकानों को नोटिस जारी कर चावल या बदले में राशि जमा करने के निर्देश दिए थे। नोटिस के बाद भी चावल-राशि जमा नहीं की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर अब इन मामलों में आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक रायपुर

नियम एक महीने में नक्शा पास कराने का, खामी बताकर लटका रहे प्रकरण

टोकन राशि से पावती देकर 1 माह के भीतर निर्धारित दस्तावेज सलंगन करने पर नक्शा पास करना है, पर धरातल पर स्थिति इसके ठीक उलट है। रायपुर नगर निगम के दस जोन स्थित 70 वार्डों में भवन अनुज्ञा पारित कराने संबंधी कार्य के लिए निगम से 1200 आर्किटेक्ट पंजीकृत हैं, जो शहरभर में आवेदकों द्वारा नक्शा पास कराने के ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित दस्तावेज की जांच कर प्रापर अपलोड करने में सहयोग करते हैं। दिक्कत फीस जनरेट करने में लेटलतीफी को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम के जोन में बैठे इंजीनियर निर्धारित दस्तावेज अपलोड होने के बाद भी पोस्ट एगुवल फीस जनरेट नहीं करते। इसके एवज में आवेदकों से अतिरिक्त राशि की अनाप-शनाप डिमांड की जाती है। इसमें

मोलभाल की शिकायत भी आ रही है। विकास शुल्क, सड़क बाधा शुल्क, 1500 वर्गफीट से अधिक के निर्माण पर रैनवाटर हॉवैस्टिंग शुल्क, उपकर के रूप में निर्माण लागत का 1 फीसदी देया। शहर के आउटर में स्थित कचना, आमासिवनी, दलदल सिवनी, सड्डू, मठपुरैना, भाठागांव, रायपुरा क्षेत्र के भूखंड मालिकों को निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराने में ज्यादा परेशानी आ रही है। इसी तरह डूंडा, वारियाखुर्द, देवपुरी में कमोबेश यही स्थिति देखी जा रही है।

कांग्रेस की अगले माह से आंदोलन की तैयारी भी स्मार्ट मीटर को लेकर हाहाकार, एमडी बोले- ज्यादा खपत की शिकायत पर पुराना मीटर लगाकर करेंगे जांच

हरिभूमि न्यूज : रायपुर



मीटर के स्थान पर पुराने मीटर लगाए जाए और तत्काल नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए। स्मार्ट मीटरों के लेकर पॉवर कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटरों को एक तो पहले से चेक किया गया है। इसी के साथ जितने स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसके अनुरूप में पांच फीसदी उपभोक्ताओं के यहां पुराने के साथ

ही स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं की पूरी संतुष्टि के बाद ही पुराने मीटर हटाए जा रहे हैं। ज्यादा बिल को लेकर जो कारण सामने आ रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बीते साल गर्मी में बिजली बिल हॉफ योजना के कारण चार सौ यूनिट तक खपत पर बिजली बिल हॉफ हो रहा है। इसमें उपभोक्ता की खपत चार सौ यूनिट से ज्यादा होने पर भी उसको लाभ मिलता था, लेकिन बीते साल अगस्त में इस योजना में संशोधन करके पहले सौ यूनिट की खपत पर बिल आधा किया गया। इसके बाद विरोध होने पर इसको बढ़ाकर दो सौ यूनिट पर बिल हॉफ किया गया। इसमें भी शर्त यह है कि खपत चार सौ यूनिट तक होनी चाहिए। गर्मी में ज्यादातर उपभोक्ताओं की खपत चार सौ यूनिट से ज्यादा होने पर बीते साल तो बिजली बिल हॉफ में हजार से 11 सौ रुपए कम हो रहे थे, वो इस बार न होने पर बिल ज्यादा लग रहा है।

शिकायत पर करेंगे जांच

स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ता की शिकायत होने पर उपभोक्ता के आवेदन पर उसके कनेक्शन के साथ पुराना मीटर लगाकर जांच की जाएगी। स्मार्ट मीटरों के जांच के बाद लगाया जा रहा है। इसमें कोई कमी नहीं है।

- भीम सिंह कंवर, एमडी वितरण कंपनी

छ.ग. सराफा एसोसिएशन

"बस्तर से अंबिकापुर एवं रायगढ़ से राजनांदगांव विकास एवं विस्तार के लिए समर्पित"



सराफा महा सम्मेलन 2026

2 साल बेमिसाल • तीसरा साल बनेगा नई मिसाल

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के वर्तमान कार्यकाल की **तृतीय** सभा

दिनांक : 28 जून 2026, रविवार स्थान : रामदेव लॉन 36 माल के बगल में, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)



मुख्य अतिथि

माननीय अरुण साव जी
उप-मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन



अति विशिष्ट अतिथि

माननीय तोखन साहू जी
केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार



अति विशिष्ट अतिथि

माननीय विजय शर्मा जी
उप-मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन



विशिष्ट अतिथि

माननीय लखन लाल देवगन जी
कैबिनेट मंत्री, छ.ग. शासन



विशिष्ट अतिथि

माननीय राजेश वर्मा जी
सांसद, खगरिया लोकसभा (बिहार)



विशेष अतिथि एवं मार्गदर्शक

अतिथिगण



माननीय अमर अग्रवाल जी
विधायक, बिलासपुर (छ.ग.)



माननीय धर्मलाल कौशिक जी
विधायक, बिल्हा (छ.ग.)



माननीय धरमजीत सिंह जी
विधायक, तखतपुर (छ.ग.)



माननीय सुराजित शुक्ला जी
विधायक, बेलतरा (छ.ग.)



माननीय अटल श्रीवास्तव जी
विधायक, कोटा (छ.ग.)



माननीय भूपेन्द्र सवनी जी
अध्यक्ष - क्रेडा



माननीय राजा पांडेय जी
अध्यक्ष-पाठ्य पुस्तक निगम



माननीय सौरभ सिंह जी
अध्यक्ष - CMDC



माननीय कृष्णकुमार बांधी जी
पूर्व विधायक, मरसुरी (छ.ग.)



माननीय सतीश धोत्रा जी
अध्यक्ष-छ.ग. वैद्य और कौन्सिल इंटरनैशनल



माननीय शिवराज भंसाली जी
आचार-सम्म-छ.ग. सराफा एसोसिएशन

-: कार्यक्रम :-

प्रथम सत्र प्रातः 10:30 बजे से

- > माननीय अतिथियों का आगमन, स्वागत, दीप प्रज्वलन
- > छ.ग. सराफा एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष का उद्बोधन
- > माननीय अतिथियों का उद्बोधन एवं मार्गदर्शन
- > जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की भूमि हेतु छत्तीसगढ़ शासन का आभार
- > स्वर्णकला बोर्ड का महत्व एवं गठन की मांग
- > धारा 317 BNS/411 IPC के दुरुपयोग रोकने हेतु व्यापारी हित सरलीकरण की माँग
- > सराफा रत्न से सम्मान संस्थापक सदस्यों, पूर्व सभी अध्यक्ष एवं सक्रिय सदस्य
- > माननीय अतिथियों का सम्मान

द्वितीय सत्र दोपहर 02:00 बजे से

- > माननीय पुलिस प्रशासन/स्थानीय शासन प्रमुख द्वारा कानून एवं सुरक्षा से संबंधित मार्गदर्शन, दिशानिर्देश एवं सुझाव
- > BIS एवं GST के प्रमुख अधिकारियों द्वारा कार्यशाला
- > नये संविधान के अनुरूप इकाई सदस्यों से एकमुस्त सदस्यता शुल्क संग्रहण आरंभ
- > खुला मंच चर्चा
- > अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से
- > सभी एसोसिएशन सदस्यों का सम्मान
- > आभार के साथ सभा का समापन

हमारा संकल्प



आयोजक : जिला बिलासपुर सराफा एसोसिएशन एवं समस्त इकाई सदस्य

कल्याण सिंह
अध्यक्ष
98933352323

दीपक सोनी
सचिव
9755638874

आलोक सोनी
कोषाध्यक्ष
89826 55220

श्रीकांत पाण्डेय
कार्यकारी अध्यक्ष
98279 24898

- बिलासपुर सराफा एसोसिएशन • तखतपुर सराफा एसोसिएशन • मस्तूरी सराफा एसोसिएशन • चकरभाठा सराफा एसोसिएशन • बिल्हा-सरागांव सराफा एसोसिएशन
- बिलासपुर सिल्वर होलसेल सराफा एसोसिएशन • सीपत सराफा एसोसिएशन • बेलतरा सराफा एसोसिएशन • करगी रोड कोटा सराफा एसोसिएशन • रतनपुर सराफा एसोसिएशन

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन



कमल सोनी

प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
9200000064



प्रकाश गोलछा

प्रदेश सचिव
9302920005



हर्षवर्धन जैन

प्रदेश कोषाध्यक्ष
7879878787



प्रदीप घोरपड़े

चेयर पर्सन
9584460707



संजय कुमार कुन्गा

कार्यकारी अध्यक्ष
रायपुर संभाग
9669811111



उत्तम चंद भंडारी

कार्यकारी अध्यक्ष
दुर्ग संभाग
7000924697



पवन अग्रवाल

कार्यकारी अध्यक्ष
बिलासपुर संभाग
9425254000



राजू दुग्गड़

कार्यकारी अध्यक्ष
बस्तर संभाग
9827411119



राजेश सोनी

कार्यकारी अध्यक्ष
सएगुना संभाग
9300023588



सुनील सोनी

संगठन मंत्री
9826121405



आलोक सोनी

मीडिया प्रभारी
8982655220

FIRST AND BIGGEST

Designer Jewellery Showroom

श्रीहृन्नी ज्वेलर्स
RAIPUR | DURG

आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

Raipur, Sadar Bazaar

+91 9584411144

Durg, Shree Shivam Mall

+91 9244509870